



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 29 जून, 2026

आषाढ़ 8, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या डीएफए/1517518/38-6003(001)/1-2026

लखनऊ, 29 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ10-433

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2025) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित योजना को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी)

योजना, उत्तर प्रदेश

अध्याय-एक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और परिभाषाएं

1-संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

1-यह योजना "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, उत्तर प्रदेश" कही जायेगी।

2-यह दिनांक 1 जुलाई, 2026 से प्रवृत्त होगी।

3-यह योजना राज्य के समस्त अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी।

2-परिभाषाएं-

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त समस्त पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 2 में उनके लिए समनुदेशित हैं।

(क) "वयस्क" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(ख) "आवेदक" का तात्पर्य किसी घर का मुखिया या उसके अन्य वयस्क सदस्य, जिसने योजना के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है, से है;

(ग) "ब्लाक" का तात्पर्य किसी जिले के भीतर किसी सामुदायिक विकास क्षेत्र से है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह समाविष्ट हो;

(घ) "केंद्र प्रायोजित योजना" का तात्पर्य किसी योजना से है, जिसमें केन्द्रीय सरकार पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्य सरकारें उसका कार्यान्वयन करती हैं;

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है, जिसे धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो;

(च) "परिवार" का तात्पर्य किसी परिवार के उन सदस्यों से है, जो रक्त, विवाह या गोद लेने से एक-दूसरे से सम्बंधित हैं और सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं और भोजन साझा करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं;

(छ) "कार्यान्वयन अभिकरण" में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई भी विभाग, जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम सम्मिलित है, जो योजना के अधीन लिए गए किसी भी कार्य के कार्यान्वयन का जिम्मा लेता है;

(ज) "मध्यवर्ती स्तर" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 के खंड (ग) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ग्राम और जिला स्तर के बीच के स्तर से है;

(झ) "राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति" का तात्पर्य धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित संचालन समिति से है;

(ञ) "मानक आवंटन" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को किया गया निधि के आवंटन से है;

(ट) "अधिसूचना" का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचना" या "अधिसूचित" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ठ) "कार्यक्रम अधिकारी" का तात्पर्य धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य राज्य के किसी क्षेत्र से है सिवाय उन क्षेत्रों के जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या स्थापित नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड द्वारा आच्छादित हो;

(ढ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों से है;

(ण) "योजना" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना से है;

(त) "राज्य" का तात्पर्य संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य से है और इसमें केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं;

(थ) "राज्य परिषद" का तात्पर्य धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद से है;

(द) "राज्य स्तरीय संचालन समिति" का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित संचालन समिति से है;

(ध) "अकुशल शारीरिक कार्य" का तात्पर्य किसी भी ऐसे शारीरिक कार्य से है, जो कोई भी वयस्क व्यक्ति बिना किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के करने में सक्षम हो;

(न) "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" का तात्पर्य जिला और राज्य स्तरों पर एकत्रित 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' से उत्पन्न प्रस्तावित कार्यों का समेकित एकत्रीकरण से है, जो अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट कार्यों के चार विषयगत क्षेत्रों के अनुरूप हो;

(प) "विकसित ग्राम पंचायत योजना" का तात्पर्य भविष्य के लिए तैयार अभिसरण-आधारित स्थानीय विकास योजना से है, जो विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा एक सहभागी और साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है और जो इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कार्यों की पहचान और प्राथमिकता के आधार के रूप में कार्य करती है;

(फ) "मजदूरी दर" का तात्पर्य धारा 10 में निर्दिष्ट मजदूरी दर से है;

(ब) "कार्य" का तात्पर्य योजना के अधीन प्रारम्भ किये गये या निष्पादित किये गये किसी कार्य से है;

अध्याय—दो

उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत

3—उद्देश्य—

(क) इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास के ढांचे को 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण (विजन) के साथ संरेखित करना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस दिनों की संवर्धित वैधानिक मजदूरी—रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

(ख) सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना, जो समेकित होकर 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' का निर्माण करते हैं; इसमें जल—सम्बंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका सम्बंधी अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान दिया जाएगा।

(ग) ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी—रोजगार की गारंटी को ध्यान में रखते हुए और कृषि के व्यस्ततम मौसम के दौरान पर्याप्त कृषि—श्रम की उपलब्धता को सुगम बनाना।

(घ) ग्राम पंचायतों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पी0एम0 गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतुष्टि—संचालित योजना और समग्र सरकारी वितरण को संस्थागत रूप देना, जो भू—स्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिला और राज्य योजना तंत्रों द्वारा संचालित है और ऐसी योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाएगा।

(ङ) एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को आधुनिक बनाना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, रीयल—टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, अग्रसक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और नियोजन, ऑडिट तथा धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सम्मिलित है।

अध्याय—तीन

गारंटी, समय सीमा और शर्तें

4—गारंटी—

(क) राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, में प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, योजना के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अन्यून एक सौ पच्चीस दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करेगी।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने योजना के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, वह प्रत्येक दिन के कार्य के लिए मजदूरी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ग) दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर किया जायेगा या किसी भी मामले में उस कार्य के किए जाने के दिनांक से अनधिक एक पखवाड़ा के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि योजना के अधीन रोजगार के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को उसके आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में उस दिनांक से जब से रोजगार मांगा गया है, जो भी बाद में हो, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

(ङ) यदि मस्टर रोल बंद होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तो मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के पश्चात के विलंब के लिए असंदत्त मजदूरी के 0.05% प्रति दिन की दर से विलंब प्रतिकर का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5—मांग के लिए शर्तें—

(1) रजिस्ट्रीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और ऐसे प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, और दिनांक के साथ एक रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा।

- (2) राज्य सक्रिय रूप से सुभेद्य समूहों की आवश्यकताओं का सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य प्रदान करेगा।
- (3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।
- (4) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में एक साथ दिए जा सकते हैं।

अध्याय—चार

नियोजन ढांचा

6—विकसित ग्राम पंचायत योजना (वी0जी0पी0पी0)—

(1) विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप एक भविष्य के लिए तैयार, अभिसरण—आधारित स्थानीय विकास योजना, ग्राम पंचायत द्वारा एक सहभागी और साक्ष्य—आधारित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाएगी और जो इस योजना के अधीन कार्यों की पहचान और प्राथमिकता के आधार के रूप में कार्य करेगी।

(2) विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित और सहभागी नियोजन अभ्यास किया जाएगा।

विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा जी0आई0एस0 आधारित उपकरणों, पी0एम0 गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को अपेक्षित आउटपुट और परिणामों के साथ सम्बंधित पंचायतों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और सभी ग्राम पंचायतों में पात्र आस्तियों और परिणामों के व्यापक कवरेज के लिए संतुष्टि—आधारित योजना के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके।

विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत—राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शहरी क्षेत्रों से निकटता सहित विकास मापदंडों के आधार पर निर्धारित अपनी श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' आदि में वर्गीकरण के अनुसार संतुष्टि—मोड योजनाएं तैयार करेगी।

ऐसे सभी कार्य विशेष रूप से 'अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना' से लिए जाएंगे, जिसे पी0एम0 गति शक्ति, जी0आई0एस0 आधारित उपकरणों और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार किया गया है।

(4) वार्षिक योजनाएं, मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(5) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में पहचाने गए कार्यों को अभिसरण में विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। ऐसे अभिसरण के लिए ली जाने वाली योजनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

(6) विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं और वार्षिक श्रम मांग तैयार करते समय, अधिसूचित मुख्य कृषि अवधियों के दौरान निष्पादन के लिए कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

7—अभिसरण और एकीकृत नियोजन के लिए ढांचा—

ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए सभी कार्यों के सुसंगत नियोजन, निष्पादन और अनुश्रवण के लिए एक 'एकीकृत अभिसरण ढांचा' स्थापित किया जाएगा, और इस उद्देश्य के लिए—

(1) अभिसरण और संतुष्टि—आधारित योजना के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं को 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' पर आधारित एक एकीकृत योजना प्रक्रिया के अधीन लाया जाएगा।

(2) सभी विद्यमान परिसंपत्तियां और प्रस्तावित कार्य, चाहे वे इस योजना के अधीन वित्त—पोषित हों या किसी अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजना के माध्यम से, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके 'विकसित भारत—राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक' के माध्यम से अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत और ट्रैक किए जाएंगे, जो ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों का एक व्यापक रजिस्टर बनाए रखेगा, कार्यों के दोहराव को रोकेगा, विभागीय निवेशों को एकीकृत करेगा और सभी कार्यों को संतुष्टि परिणामों के साथ संरेखित करेगा।

(3) ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकल डिजिटल बैकबोन उपलब्ध होगा जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से सम्बंधित अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्य सम्मिलित होंगे;

और सभी नियोजन विकसित ग्राम पंचायत योजना की तैयारी से शुरू होकर एक कठोर 'नीचे से ऊपर की ओर' प्रक्रिया का पालन करेंगे, जिसे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर क्रमिक रूप से संकलित किया जाएगा, और संकलित राज्य योजना को अनुमोदन के लिए 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' के समक्ष रखा जाएगा।

वार्षिक योजनाएं मानकीय आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(4) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक राज्यों, जिलों और पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिकता वाले अवसंरचना के अंतरालों की पहचान करने, कार्यों के डिजाइनों को मानकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करेगा कि सार्वजनिक निवेश ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर संतृप्ति के परिणामों में मापने योग्य योगदान करेगा।

(5) यह संस्थागत संरचना एक 'एकल-योजना, बहु-वित्तपोषण' दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी, विभागों और योजनाओं में अभिसरण को बढ़ावा देगी, और सभी ग्रामीण विकास प्रयासों को 'विकसित भारत @2047' के विजन के साथ संरेखित करेगी ताकि उत्पादक, सुदृढ़ और परिवर्तनकारी ग्रामीण आस्तियों का निर्माण किया जा सके।

अध्याय –पांच

राज्य संस्थागत संरचना

8-राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद-

(1) राज्य स्तर पर एक राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद होगी, जिसे "उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद" कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की एक राज्य स्तरीय साधारण सभा होगी जिसमें निम्नलिखित पदधारक/सदस्य सम्मिलित होंगे:

1	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2	मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
3	मंत्रीगण, वित्त, राजस्व, वन, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, कृषि, नियोजन, पंचायती राज, न्याय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण अभियंत्रण, पशुधन, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, समाज कल्याण, श्रम	सदस्य
4	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, राजस्व, वन, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, कृषि, नियोजन, पंचायती राज, न्याय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण अभियंत्रण, पशुधन, उद्यान, मत्स्य सहकारिता, समाज कल्याण, श्रम, विधायी विभाग और अन्य, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	आयुक्त, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
7	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 अशासकीय सदस्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि	सदस्य

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन नामनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों में से अन्यून एक तिहाई महिलाएं होगी:

परन्तु यह और कि अशासकीय सदस्यों में से अन्यून एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित होने चाहिए।

(2) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन राज्य परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए, तथा परिषद की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) नियम के रूप में पृथक से अधिसूचित की जाएगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के कर्तव्य एवं कृत्य:

(एक) राज्य सरकार को, योजना और राज्य में इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना;

(दो) समय-समय पर निगरानी और निवारण तंत्र की समीक्षा करना और सुधारों की सिफारिश करना;

(तीन) राज्य में अधिनियम और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना और केंद्रीय परिषद के साथ ऐसे कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(चार) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(पांच) केंद्रीय परिषद या राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करना।

(4) राज्य परिषद को राज्य में चल रही योजना का मूल्यांकन करने का अधिकार होगा और उस उद्देश्य के लिए राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और योजना एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े एकत्र करने या एकत्र करवाने का अधिकार होगा।

9-राज्य स्तरीय संचालन समिति—

(1) राज्य स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करने, समन्वय करने और निगरानी करने हेतु एक राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी।

1	राज्य के मुख्य सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव के रैंक से अनिम्न रैंक के अधिकारी द्वारा	अध्यक्ष
2	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
3	आयुक्त, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन योजना (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव
4	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, वित्त, राजस्व, वन, सिंचाई एवं जल संसाधन, लोक निर्माण, कृषि, नियोजन, पंचायती राज, न्याय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण अभियंत्रण, पशुधन, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, समाज कल्याण, श्रम, विधायी और अन्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	विषय-विशेषज्ञों की इतनी संख्या, जितनी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए	सदस्य
6	तकनीकी या अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि	सदस्य
7	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य	सदस्य

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति:—

(एक) राज्य-व्यापी नियोजन और अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय की निगरानी करेगी;

(दो) जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और समेकित राज्य योजना को समय पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी;

(तीन) राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय करेगी और वहां से जारी किए गए निदेशों का क्रियान्वयन करेगी;

(चार) राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रियागत सुधारों का समर्थन करेगी; और

(पांच) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा उसे समुनदेशित किये जाएं।

10-मध्यवर्ती पंचायतें-

1-जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर की पंचायतें इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी योजना के नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए प्रमुख प्राधिकरण होंगी।

2-जिला स्तर पर पंचायत, जिले में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख और समन्वय करेगी, जिसमें समग्र जिला स्तरीय योजना को अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना, कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण, समन्वय सुनिश्चित करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जाय, सम्मिलित है।

3-मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, समग्र ब्लॉक स्तरीय योजना तैयार करेगी और अंतिम रूप देगी, ग्राम पंचायतों को योजना और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगी।

4-वार्षिक योजनाएं मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएगी।

5-ग्राम पंचायत, परिवारों का रजिस्ट्रीकरण करेगी, कार्यों के लिए आवेदन का प्रक्रमण करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार करेगी, उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगी, राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और योजना के अधीन उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगी।

11-जिला कार्यक्रम समन्वयक-

1-जिला कलेक्टर को जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए 'जिला कार्यक्रम समन्वयक' के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2-जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस योजना के प्रावधानों और तद्दीन बनाए गए नियमों के अनुसार जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

3-जिला कार्यक्रम समन्वयक के कृत्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-

(एक) जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला समेकित योजना के समेकन और उसे अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला स्तर पर योजना के समन्वयन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण की निगरानी करेगा;

(दो) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस योजना के उपबंधों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और योजना के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यथा आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां और मंजूरी प्रदान करेगा, जिनमें डिजिटल, भू-स्थानिक और अनुश्रवण प्रणालियों से सम्बंधित स्वीकृतियां सम्मिलित हैं;

(तीन) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा, और अधिनियम एवं योजना के अधीन स्थापित अनुश्रवण ढांचे, प्रबंधन सूचना प्रणाली और उत्तरदायित्व तंत्र का उपयोग करते हुए उनके प्रदर्शन की समीक्षा, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करेगा;

(चार) जिला कार्यक्रम समन्वयक, योजना के अधीन किए गए कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता और उत्पादकता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी/अधिसूचित नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेगा।

4-जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपने अधिकारिता के अधीन अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं, समेकित ब्लॉक योजनाओं और जिला पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करके जिले के लिए एक समेकित योजना तैयार करेगा।

12-कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक स्तर)-

1-प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी को मध्यवर्ती स्तर की पंचायत हेतु कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

2-कार्यक्रम अधिकारी अधिनियम और उसके तद्दीन बनाई गई योजना के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत की सहायता करेगा।

3-कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में कार्यों से उत्पन्न रोजगार के अवसरों के साथ रोजगार की मांग का मिलान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4-कार्यक्रम अधिकारी अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लॉक के लिए एक समेकित योजना तैयार करेगा।

5-उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यक्रम अधिकारी के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(एक) ब्लॉक के भीतर विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए सभी कार्यों और परियोजनाओं का अनुश्रवण करना;

(दो) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र परिवारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना;

(तीन) ब्लॉक के भीतर योजना के अधीन नियोजित सभी मजदूरों को शीघ्र और उचित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना, जिसमें डिजिटल और बायोमेट्रिक अधिप्रमाणित भुगतान प्रणाली जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, के माध्यम से है;

(चार) सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा ऐसे लेखा परीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और निष्कर्षों पर समय पर उचित कार्यवाही की जाती है;

(पांच) ब्लॉक के भीतर योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित सभी परिवादों और शिकायतों का इस अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से तत्परता से कार्यवाही करना;

(छः) ब्लॉक के भीतर सभी कार्यों का जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग तथा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुश्रवण, उत्पादकता और पारदर्शिता ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(सात) ब्लॉक स्तर पर संतृप्ति आधारित नियोजन तथा योजना के अधीन कार्यों के निष्पादन का समर्थन देने हेतु अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाना;

(आठ) कोई अन्य कृत्य जैसा कि जिले द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय।

(नौ) इस अधिनियम के अधीन कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार।

6-कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण में अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।

13-ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व-

ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-

(एक) परिवारों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना;

(दो) कार्य के आवेदन प्राप्त करना और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों के अभिलेख अनुरक्षित रखना;

(तीन) विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार करना;

(चार) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, कार्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, संतृप्ति के आधार पर एक 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' तैयार करेगी;

(पांच) वार्षिक योजनाएं 'मानक आवंटन' के आधार पर तैयार की जाएंगी;

(छः) कार्यक्रम अधिकारी लागत के संदर्भ में योजना के अधीन न्यूनतम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने हेतु आवंटित करेगा;

(सात) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित की आपूर्ति करेगा:-

(क) इसके द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए स्वीकृत कार्यों हेतु मस्टर रोल;

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूची।

(आठ) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार के अवसरों का आवंटन करेगी और उन्हें कार्य हेतु रिपोर्ट करने के लिए कहेगी;

(नौ) योजना के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए कार्य आवश्यक तकनीकी मानकों और मापों के अनुरूप होंगे;

(दस) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का निष्पादन करना; और

(ग्यारह) एक ग्राम पंचायत 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' से ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर योजना के अधीन कोई भी कार्य ले सकती है, जैसा कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए।

14-ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा-

1-ग्राम सभा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर योजना के अधीन किए गए सभी कार्यों के निष्पादन का अनुश्रवण और समीक्षा करेगी।

2-ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर योजना के अधीन लिए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी/अधिसूचित किया गया हो।

3-ग्राम पंचायत, सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक सभी अभिलेख और दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी, जिनमें मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिकाएं, स्वीकृति आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो टैग किए गए फोटो और खाते की अन्य सभी सम्बंधित पुस्तकें और कागजात सम्मिलित हैं, चाहे वे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित हो।

अध्याय-छः

रजिस्ट्रीकरण और रोजगार गारंटी कार्ड

15-परिवारों का रजिस्ट्रीकरण-

1-परिवार रजिस्ट्रीकरण-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक है, रजिस्ट्रीकरण और 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी करने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वे रहते हैं, में अपने परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पता प्रस्तुत कर सकता है।

2-विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, जहाँ रोजगार इच्छुक निम्नलिखित में से है -

- (क) एकल महिला; या
- (ख) दिव्यांग व्यक्ति; या
- (ग) साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति; या
- (घ) एक मुक्त बंधित श्रमिक; या
- (ङ) विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह से सम्बंधित व्यक्ति; या
- (च) ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

3-एक अलग रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन और कार्यस्थल की सुविधाओं, जैसा लागू हो, में विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

16-ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना-

1-यह ग्राम पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि उपयुक्त समझे, ऐसा आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी करे, जिसमें एक परिवार के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों का विवरण, उनके फोटो, बैंक या डाकघर खाता संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और आधार संख्या, यदि कोई हो सहित अद्वितीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य संख्या अंतर्विष्ट हो।

2-जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड तीन साल के लिए वैध होगा।

3-जिसके पश्चात उचित सत्यापन के उपरांत इसका नवीकरण किया जा सकता है।

4-कोई भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार के सिवाय रद्द नहीं किया जाएगा-

- (एक) जहाँ यह द्विप्रतिक पाया जाता है;
- (दो) जहाँ पूरा परिवार स्थायी रूप से ग्राम पंचायत की अधिकारिता से बाहर प्रव्रजन कर गया हो, और अब गांव में नहीं रहता हो; या
- (तीन) जहाँ रजिस्ट्रीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो गई हो।

5-राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में नियमित रूप से निम्नलिखित विवरणों को योजना के अधीन निम्नानुसार मुख्य गारंटियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अद्यतन करने की व्यवस्था करेगी:-

- (एक) उन दिनों की संख्या जिनके लिए कार्य की मांग की गई थी;
- (दो) आवंटित कार्य के दिनों की संख्या;
- (तीन) मस्टर रोल संख्या सहित आवंटित कार्य का विवरण;

- (चार) माप का विवरण;
 (पांच) भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो;
 (छः) भुगतान की गई मजदूरी की दिनांक-वार राशि;
 (सात) भुगतान किया गया विलंब प्रतिकर, यदि कोई हो;
 (आठ) प्रदान की गई परिसंपत्ति, यदि कोई हो।

6-प्रत्येक श्रमिक को सुनवाई किये जाने का और योजना के अधीन शिकायत निवारण तंत्र के उपबंधों के अनुसार निपटान हेतु, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत रजिस्टर कराने का अवसर होगा।

17-विस्थापन की स्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना-

1-इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप जैसी किसी भी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य:-

(एक) अस्थायी पुनःस्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण और 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी करने की मांग कर सकते हैं;

(दो) अस्थायी पुनःस्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं; और

(तीन) कार्ड के खो जाने या नष्ट होने की स्थिति में पुनः रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2-ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का विवरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित किया जाएगा।

3-सामान्य स्थिति बहाल होने पर, इस प्रकार जारी किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को मूल निवास स्थान पर पुनः पृष्ठांकित किया जाएगा और मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त होने पर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा।

4-प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या को प्रति परिवार 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार की गणना करते समय गिना जाएगा।

अध्याय-सात

कार्य की मांग और आवंटन

18-कार्य की मांग-

1-किसी रजिस्ट्रीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और ऐसे प्रत्येक आवेदन का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, तथा दिनांक सहित जारी रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिये गये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा।

2-राज्य सरकार सुभेद्य समूहों की आवश्यकताओं की सक्रिय जांच करेगी और उन्हें कार्य प्रदान करेगी।

3-कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है और यह आवेदन वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

4-कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में एक साथ दिया जा सकता है।

5-किसी व्यक्ति द्वारा आवेदित रोजगार के दिनों की संख्या या उसे वास्तव में दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर परिवार की कुल गारंटी के अध्वधीन कोई सीमा नहीं होगी।

6-सामान्यतः कार्य के लिए आवेदन न्यूनतम 6 दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए।

7-योजना में अग्रिम आवेदन की व्यवस्था होगी, अर्थात् जिस दिनांक से रोजगार चाहिए उससे पहले भी आवेदन दिया जा सकता है।

8-एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन जमा करने का योजना में उपबंध किया जाएगा, परन्तु यह कि वे अवधियां जिनके लिए रोजगार मांगा गया है, आपस में अतिव्यापी न हों।

19-कार्य का आवंटन-

1-ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदक को योजना के उपबंधों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के दिनांक या अग्रिम आवेदन की स्थिति में जिस दिनांक से कार्य चाहा गया हो, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा।

2-महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि रजिस्ट्रीकृत और कार्य मांगने वाली लाभार्थियों में न्यूनतम एक-तिहाई महिला लाभार्थी हों। एकल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

3-आवेदक, जिन्हें कार्य प्रदान किया गया है, उनको लिखित रूप में सूचना ग्राम रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए पते पर उन्हें प्रेषित पत्र के माध्यम से या किसी अन्य प्रभावी संचार माध्यम से या जिला, मध्यवर्ती या ग्राम पंचायत के कार्यालय में सार्वजनिक नोटिस लगाकर दी जायेगी।

4-जिन व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है, उनकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे और यह सूची राज्य सरकार तथा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

5-यथासम्भव, आवेदन के समय आवेदक के निवास वाले गांव से 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर ही रोजगार प्रदान किया जाएगा।

6-योजना के अधीन नया कार्य तब शुरू किया जा सकता है जब न्यूनतम 10 श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हों, परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा यथाअवधारित, पहाड़ी क्षेत्रों में और वृक्षारोपण सम्बंधी कार्यों के सम्बंध में नये कार्यों में यह शर्त लागू नहीं होगी।

7-यदि 5 किलोमीटर की त्रिज्या से बाहर कार्य प्रदान किया जाता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और रहने-खाने के खर्च के लिए मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जायेगा।

8-रोजगार की अवधि एक सप्ताह में छह दिन से अधिक न होने के साथ न्यूनतम छह दिन निरंतर होगी।

अध्याय- आठ

मस्टर रोल, उपस्थिति और मापन**20-मस्टर रोल-**

इस योजना के अधीन किए गए कार्यों के लिए मस्टर रोल डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अनुरक्षित किए जाएंगे और निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे-

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होगा और इसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट पहचान संख्या (ई-मस्टर) होगी।

(ख) मस्टर रोल में उन सभी श्रमिकों के नाम सम्मिलित होंगे, जिन्होंने काम की मांग की है या जिन्हें काम आवंटित किया गया है और इसे ग्राम पंचायत के प्राधिकृत पदाधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

21-उपस्थिति दर्ज करना-

कार्यस्थल पर उपस्थिति एक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणालियों का उपयोग करके दैनिक रूप से दर्ज की जाएगी, और समस्त उपस्थिति विवरण दैनिक आधार पर नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक रूप से देखने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

22-कार्य का मापन-

1-मजदूरी संदाय केवल कार्यस्थल पर अधिकृत तकनीकी कार्मिकों द्वारा मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर किए गए मापन के आधार पर किया जाएगा, और इसे निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल रूप से अभिलेखित किया जाएगा।

2-राज्य सरकार समय पर मापन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी कार्मिकों का अभिनियोजन सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त व्यक्तियों को प्रत्यायोजित तकनीकी जिम्मेदारियों के साथ, प्रशिक्षित किया जायेगा और अभिनियोजित किया जाएगा, तथा उन्हें कुशल दरों पर मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

अध्याय — नौ

मजदूरी संदाय और विलंब प्रतिकर

23—मजदूरी संदाय—

1- कर्मकार को संदाय की जाने वाली मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा विनिश्चित और अधिसूचित की जाएगी।

2- दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में, ऐसे कार्य किए जाने के दिनांक से अनधिक एक पखवाड़ा में किया जाएगा।

24—संदाय का तरीका—

मजदूरी का संदाय, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, संबंधित बैंकों या डाकघरों में कर्मकारों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

25—विलंब प्रतिकर—

1—यदि मस्टर रोल बंद होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तो मजदूरी मांगने वाले मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के पश्चात, विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए, असदत्त मजदूरी का 0.05% प्रतिकर पाने के हकदार होंगे।

2—प्रतिकर के संदाय में संदेय के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक का विलंब मजदूरी के संदाय में विलंब के समान ही माना जाएगा।

3—मजदूरी संदाय में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभिन्न कृत्यकारियों या अभिकरणों की जिम्मेदारी तय करने के प्रयोजन से, राज्य मजदूरी के निर्धारण और संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित करेंगे, जैसे—

(एक) कार्य का मापन;

(दो) मस्टर रोल का कंप्यूटरीकरण;

(तीन) मापन का कंप्यूटरीकरण;

(चार) मजदूरी सूची तैयार करना; और

(पांच) निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) को अपलोड करना; और

विनिर्दिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए जिम्मेदार कृत्यकारियों या अभिकरणों के साथ चरण-वार अधिकतम समय सीमा विनिर्दिष्ट करेंगे।

4—कम्प्यूटर प्रणाली में मस्टर रोल के बंद होने के दिनांक और मजदूरी मांगने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने के दिनांक के आधार पर संदेय प्रतिकर की स्वचालित गणना का उपबंध होगा।

5—जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सम्यक सत्यापन के बाद अग्रिम रूप से प्रतिकर मुआवजे का संदाय करेंगे और संदाय में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कृत्यकारियों या अभिकरणों से प्रतिकर की धनराशि की वसूली करेंगे।

6—विलंब के दिनों की संख्या, संदेय प्रतिकर और वास्तविक संदाय प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाएगा।

अध्याय — दस

बेरोजगारी भत्ता

26—पात्रता—

1—यदि योजना के अधीन रोजगार के लिए किसी आवेदक को, उसके रोजगार मांगने के आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस दिनांक से रोजगार मांगा गया है, जो भी बाद में हो, ऐसा रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

2—ऐसी कोई भी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगी।

27—प्रक्रिया—

आवेदक के परिवार को संयुक्त रूप से संदेय बेरोजगारी भत्ता, कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकरण (जिसमें जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर की पंचायत सम्मिलित है) द्वारा मंजूर और संवितरित किया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उसके संदाय के लिए देय होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा।

अध्याय — ग्यारह

कार्यों की श्रेणियां और व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों के लिए पात्रता मानदंड

28—योजना के अधीन कार्य और श्रेणियां—

1—योजना का केन्द्र बिन्दु—कार्यों का वर्गीकरण: योजना उन कार्यों की श्रेणियों पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिनकी पहचान विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में की गई है और जिन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में संकलित किया गया है।

2—योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य, साथ ही उनके केन्द्रीय विषय और अभीष्ट निष्कर्ष निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन आएंगे:—

क— श्रेणी एक—जल सम्बंधी कार्य (जल सुरक्षा के लिए)—

(क) इसमें संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, स्रोत सततता, जल निकायों का पुनरुद्धार, जलसंभर विकास और वृक्षारोपण को केन्द्रबिन्दु में सम्मिलित किया जायेगा तथा दृष्टांत रूप में किये जाने वाले कार्यों में सम्मिलित हैं:—

(एक) नहरों, बाढ़ या डायवर्जन चौनल, चेक डैम, गली प्लग और भूमिगत डाईक का निर्माण;

(दो) तालाबों, अंतःस्रवण (पर्कॉलेशन) टैंक, पुनर्भरण गड्ढों, पुनर्भरण कूपकों, अन्तःक्षेपक कूपों और सम्बंधित जल संचयन संरचनाओं का निर्माण या नवीकरण;

(तीन) सिंचाई के लिए खुले कुएं, सूक्ष्म-सिंचाई चौनल और खेत जल वितरण प्रणाली;

(चार) सामुदायिक जलभराव वाली भूमि का पुनरुद्धार;

(पांच) मृदा एवं नमी संरक्षण से संबद्ध वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्य;

(छः) छतों पर वर्षा जल संचयन और अन्य विकेंद्रीकृत;

(सात) पुनर्भरण प्रणालियां।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलन क्षमता के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, पुनर्भरण और संरक्षण के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना।

ख— श्रेणी दो—मूल ग्रामीण अवसंरचना—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सम्पर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मूलभूत नागरिक, सामाजिक, शासन एवं सेवा-प्रदाय अवसंरचना सम्मिलित होगी तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों (Illustrative works) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(एक) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, आर-पार जल निकास, संरचनाओं और ग्रामीण सम्पर्क सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन;

(दो) ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्रामीण पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण;

(तीन) विद्यालय अवसंरचना का निर्माण, जिसमें किचन शेड, अतिरिक्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, चहारदीवारी एवं खेल मैदान सम्मिलित हैं;

(चार) श्मशान घाट और सामुदायिक अवसंरचना;

(पांच) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियां जिसमें स्थिरीकरण तालाब, सामुदायिक शौचालय परिसर और अपशिष्ट पृथक्करण तथा संग्रहण केंद्र सम्मिलित हैं;

(छः) सौर प्रकाश प्रणालियां और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना की स्थापना;

(सात) ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, परिवहन शेड और अन्य सामान्य ग्रामीण सुविधाएं;

(आठ) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अधीन अनुमत ग्रामीण आवास कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अधीन अनुज्ञेय कार्य भी सम्मिलित हैं;

(नौ) जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अधीन किए गए कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण में, बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सेवा पहुंच और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(ग) श्रेणी तीन—आजीविका सम्बंधी अवसंरचना—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं में ऐसी उत्पादक परिसंपत्तियां और सुविधाएँ सम्मिलित होंगी जो कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, मूल्य संवर्धन, कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को समृद्ध करें तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं:

(एक) प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केंद्रों और आजीविका गतिविधियों के लिए वर्क शेड का निर्माण;

- (दो) ग्रामीण हाट अथवा साप्ताहिक बाजार और अन्य बाजार अवसंरचना;
- (तीन) खाद्यान्न भंडारण भवन, कृषि उत्पाद भंडारण संरचनाएं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट और अन्य कृषि मूल्य शृंखला अवसंरचना;
- (चार) स्वयं-सहायता समूहों (SHG) और संघ-स्तरीय संस्थाओं के लिए भवन;
- (पांच) वर्मी कम्पोस्ट और एन ए डी ई पी यूनिट सहित कंपोस्ट संरचनाएँ;
- (छः) वृक्ष-पशुचारण घास के मैदान का विकास, डेयरी अवसंरचना और पशु, बकरी, सूअर, मुर्गी और अन्य पशुधन का आश्रय;
- (सात) मछली सुखाने के प्रांगड समेत मत्स्य पालन सम्बंधी अवसंरचना;
- (आठ) पौधशालाओं का विकास और निर्माण सामग्री उत्पादन;
- (नौ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परिचालित और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रतिरूपण को बढ़ावा देने वाले एकीकृत प्रोजेक्ट(परियोजनाएँ)।
- (ख) अभीष्ट निष्कर्ष— सतत आजीविका, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सुदृढीकरण।
- (ग) श्रेणी चार-चरम मौसम सम्बंधी घटनाओं का न्यूनीकरण और आपदा-पूर्व तैयारी के लिए विशेष कार्य—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, तथा ग्रामीण समुदायों और परिसंपत्तियों को बाढ़, चक्रवातों, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना सम्मिलित होगा तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं,—

(एक) चक्रवात आश्रयों, बाढ़ आश्रयों और बहुउद्देशीय आपदा-प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण;

(दो) जल मोड नहरों, तटबंध का निर्माण और अन्य आपदा-न्यूनीकरण कार्य;

(तीन) बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाबों एवं जल संरचनाओं का स्थिरीकरण;

(चार) आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों, पुनर्वास, पुनर्स्थापन तथा मरम्मत;

(पांच) पवन-रोधी और आश्रय-पट्टी वृक्षारोपण;

(छह) अग्नि सहित वनाग्नि प्रबंधन कार्य;

(सात) अवरोधकों, ईंधन बफर क्षेत्र तथा संबंधित उपाय।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष— चरम मौसमीय परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम जलवायु —लचीले ग्रामों का निर्माण।

3-केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य।

4-अधिनियम के अधीन बनाई गई ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

5-व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अधीन आवास सम्बंधी कार्य, स्वच्छता सम्बंधी कार्य और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन संचालित एवं इस योजना में सम्मिलित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिसूचित अन्य लाभार्थीपरक विकासात्मक कार्य सम्मिलित हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार की सम्बंधित योजनाओं के अधीन निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी, साथ ही ऐसे समस्त कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मानदंडों, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप होंगे।

29-व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य के लिए लाभार्थी की पात्रता मानदंड—

उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तिगत परिसंपत्ति सृजन वाले कार्यों को उन परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या वास स्थान पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो निम्न श्रेणियों से सम्बंधित हैं:

(एक) अनुसूचित जातियाँ;

(दो) अनुसूचित जनजातियाँ;

(तीन) घुमंतू जनजातियाँ;

(चार) विमुक्त जनजातियाँ;

(पांच) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

(छः) महिला—प्रधान परिवार;

(सात) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित परिवार;

(आठ) भूमि सुधार के लाभार्थी;

(नौ) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण(PMAY-G) के लाभार्थी; और

(दस) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन लाभार्थी और उपर्युक्त श्रेणियों के अधीन पात्र लाभार्थियों के निःशेष होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लघु एवं सीमांत किसानों की भूमि पर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के अधधीन कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें यह आवश्यक शर्त भी सम्मिलित है कि ऐसे परिवारों के पास वैध जॉब कार्ड हो तथा उनकी भूमि या वास—स्थान पर किए जाने वाले कार्य में कार्य करने के लिए परिवार का कम से कम एक सदस्य इच्छुक हो।

अध्याय—बारह

कार्यस्थल प्रबंधन और सुरक्षा

30—कार्यस्थल पर सुविधाएं—

1—कार्यस्थल पर पारदर्शिता के प्रयोजन से, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा—

(एक) एक परियोजना प्रारंभ बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें श्रमिकों को कार्य के विभिन्न उपबंधों के बारे में समझाया जाएगा;

(दो) मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी;

(तीन) प्रत्येक कार्य का मापन अभिलेख और श्रमिकों का ब्यौरा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा;

(चार) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक 'नागरिक सूचना बोर्ड' लगाया जाएगा ;

(पांच) इसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा; और

(छः) केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति सभी कार्यों की जाँच कर सकती है और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में 'कार्य रजिस्टर' में दर्ज की जाएगी और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

2—कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया और विश्राम की अवधि, मामूली चोटों और किए जा रहे कार्य से सम्बंधित अन्य स्वास्थ्य खतरों के आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

3—यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ आने वाले पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन्हीं महिला श्रमिकों में से एक को प्रतिनियुक्त करने का उपबंध किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर का संदाय किया जाएगा।

31—सुरक्षा और दुर्घटनाएं—

1—यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजन के दौरान और उससे सम्बंधित किसी दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो वह आवश्यकतानुसार निःशुल्क चिकित्सा उपचार का हकदार होगा।

2—जहाँ घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो वहाँ राज्य सरकार आवास, उपचार, दवाओं और दैनिक भत्ते जो मजदूरी दर के आधे से कम न हो के संदाय सहित ऐसे चिकित्सालय में भर्ती की व्यवस्था करेगी।

3—यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे या उसके कानूनी वारिसों को यथास्थिति कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अधीन हकदारी के अनुसार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुग्रह राशि का संदाय किया जाएगा।

4-यदि योजना के अधीन नियोजित व्यक्ति के साथ आए किसी बच्चे को दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा उपचार का हकदार होगा; और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में, राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित कानूनी संरक्षकों को अनुग्रह राशि का संदाय किया जाएगा।

अध्याय – तेरह

कृषि के मुख्य मौसम के दौरान किए जा रहे कार्यों पर निर्बन्धन

32-प्रमुख कृषि मौसमों की अधिसूचना-

राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले, एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर साठ दिनों की अवधि या अवधियों को अधिसूचित करेगी, जिसमें बुवाई और कटाई के प्रमुख कृषि मौसम शामिल होंगे; इस अवधि के दौरान योजना के अधीन कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

33-क्षेत्र-विशिष्ट अधिसूचनाएं-

1-राज्य सरकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें जिले, ब्लॉक या ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं, के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर सकती है-

(एक) कृषि-जलवायु क्षेत्र;

(दो) कृषि गतिविधियों के स्थानीय प्रतिरूप; और

(तीन) ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

2-इस उपबंध के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना का अधिनियम और योजना के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी प्रभाव होगा।

34-अधिसूचित अवधियों के दौरान कार्यों पर प्रतिषेध-

योजना के तहत कार्यों के नियोजन, स्वीकृति या निष्पादन के लिए उत्तरदायी समस्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित प्रमुख कृषि मौसमों के दौरान कोई भी कार्य शुरू न किया जाए।

35-कार्यों का समय-निर्धारण-

कार्यक्रम अधिकारी और अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी, समेकित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को अनुमोदित करते समय और कार्यों का समय निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त कार्य केवल अधिसूचित प्रमुख कृषि मौसमों के बाहर ही लिए जाएं।

अध्याय-चौदह

प्राक्कलन, स्वीकृति और कार्य निष्पादन

36-प्राक्कलन-

1-कार्यों के लिए तकनीकी प्राक्कलन और मानक- इस योजना के अधीन प्रत्येक कार्य के लिए विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप रूपरेखा के आधार पर तैयार किए गए तकनीकी प्राक्कलन और डिजाइन को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

2-निर्माण से सम्बंधित कार्यों के लिए, श्रमिकों की उपलब्धता और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग के आधार पर, जहाँ तक संभव हो, उपयुक्त श्रम-प्रधान प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा।

3-सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 'मात्रा विवरण' में स्पष्ट और सामान्यतः समझी जाने वाली शब्दावली का उपयोग किया जाएगा।

4-प्रत्येक कार्य में प्राक्कलन का सारांश, डिजाइन और एक तकनीकी नोट होगा, जो अपेक्षित आउटपुट और परिणामों को दर्शाएगा।

5-समस्त तकनीकी प्राक्कलन, डिजाइन और परिणाम नोट, नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से तैयार या अपलोड किए जाएंगे।

37-प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां-

1-ग्राम पंचायत स्तर पर 'अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना' के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर समेकित किए गए कार्यों को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार और तीस दिनों के भीतर प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2-स्वीकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

(एक) प्रस्तावित कार्य विशेष रूप से 'अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना' से ही लिए गए हैं;

- (दो) वार्षिक योजनाएं मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी;
- (तीन) कार्य विषयगत क्षेत्रों और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप हैं;
- (चार) समस्त स्वीकृत कार्य अधिनियम के अधीन नाम निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं।

38—आउटपुट (उत्पादन) के साथ मजदूरी का जुड़ाव और दर अनुसूची—

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के मजदूरी को पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ा जाए तथा उसका निर्धारण विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न मौसमों के लिए 'समय-और-गति अध्ययन' के आधार पर अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित 'ग्रामीण दर अनुसूची' के अनुसार होगा।

39—कमजोर समूहों के लिए दर की विशेष अनुसूची—

महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्बल करने वाली बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के कार्यों में उनकी उत्पादक सहभागिता को सुकर बनाने हेतु एक अलग 'दर की अनुसूची' को अंतिम रूप दिया जाएगा।

40—कार्य के घंटे और उपार्जन मानक—

1—दर की अनुसूची इस प्रकार विरचित की जाएगी कि आठ घंटे कार्य करने वाला एक वयस्क व्यक्ति, जिसमें एक घंटे का विश्राम सम्मिलित हो अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य रकम उपार्जित कर सके।

2—एक वयस्क श्रमिक के कार्य के घंटे लचीले(Flexible) हो सकते हैं, लेकिन वे विश्राम के अन्तरालों सहित एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तारित नहीं होंगे।

41—निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण—

राज्य सरकार, गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, मापों की सटीकता और वास्तव में निष्पादित कार्य की मात्रा के साथ मजदूरी भुगतान की अनुरूपता का सत्यापन करने के लिए नाम निर्दिष्ट गुणवत्ता-नियंत्रण टीमों द्वारा कार्यों के नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड की जाएगी।

42—प्रगतिरत कार्यों की समाप्ति—

नए कार्यों को प्रारंभ करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियोजन मानकों और अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अधीन रहते हुए, प्रगतिरत (Ongoing) या अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता दी जाए।

43—मजदूरी-सामग्री अनुपात—

ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजनान्तर्गत किए गए सभी कार्यों के लिए, जिला स्तर पर सामग्री घटक की लागत चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

44—ठेकेदारों के बिना निष्पादन—

1—इस अधिनियम के अधीन व्यय के माध्यम से वित्तपोषित किसी भी कार्य या उसके घटक के निष्पादन के लिए किसी भी ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्य योजना के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्षतः निष्पादित किए जाएंगे, जिसमें अनिवार्य स्वतः प्रकटीकरण और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है।

2—अभिसरण के मामलों में, जहाँ किसी कार्य के घटकों को अन्य योजनाओं के अधीन वित्तपोषित किया जाता है, उन घटकों का निष्पादन अभिसरण करने वाली योजना के मानकों के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें अनुज्ञा प्राप्त होने पर ठेकेदारों का उपयोग भी सम्मिलित है।

3—जहाँ तक हो सके यथासाध्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके किए जाएंगे और ऐसी किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा जो श्रम को विस्थापित करती हो।

45—सामग्रियों का पारदर्शी उपापन—

कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का उपापन ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पारदर्शी उपापन प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई-निविदा प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी।

अध्याय —पन्द्रह

फंडिंग पैटर्न और वित्तीय व्यवस्था

46—वित्तपोषण स्वरूप—

1—केन्द्रीय प्रायोजित योजना— इस योजना को एक 'केन्द्रीय प्रायोजित योजना' के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

2—केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत का हिस्सा बांटना (Cost Sharing),—

(क) योजना के अधीन वित्तपोषण का स्वरूप निम्नलिखित होगा:—

(एक) उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10; और

(दो) अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 ।

(ख) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार योजना का पूर्ण व्यय वहन करेगी।

47—वित्तीय व्यवस्थाएं—

1—राज्य—वार मानक आवंटन— केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, समय-समय पर सूचित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य—वार मानक आवंटन अवधारित करेगी।

2—मानक आवंटन से अधिक व्यय: राज्य—वार मानक आवंटन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी व्यय राज्य सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

3—केंद्रीय अंश: अनुमोदित आवंटन के भीतर, केन्द्रीय सरकार के अंश में किया गया व्यय सम्मिलित किया जायेगा—

(क) योजना के अधीन नियोजित अकुशल(Unskilled), अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) और कुशल श्रमिकों (Skilled) की मजदूरी का संदाय;

(ख) अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट के अधीन, कार्यों का सामग्री घटक; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्रशासनिक व्यय जिनमें सम्मिलित हैं—

(एक) कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(दो) केंद्रीय परिषद के प्रशासनिक व्यय;

(तीन) अनुसूची—दो के अधीन आवश्यक सुविधाएं; और

(चार) ऐसी अन्य मदें।

4— राज्य अंश— अनुमोदित आवंटन के भीतर, राज्य सरकार के अंश के मद में किया गया व्यय सम्मिलित होगा—

(क) योजना के अधीन नियोजित अकुशल (Unskilled), अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) और कुशल (Skilled) श्रमिकों की मजदूरी का संदाय;

(ख) अनुसूची—एक के अधीन, कार्यों का सामग्री घटक; और

(ग) जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसे प्रशासनिक व्यय, जिनमें सम्मिलित हैं—

(एक) कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(दो) राज्य परिषद के प्रशासनिक व्यय;

(तीन) अनुसूची—दो के अधीन आवश्यक सुविधाएं; और

(चार) ऐसी अन्य मदें।

5—बेरोजगारी भत्ता और विलंब प्रतिकर— राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी किए गए उपबंधों के अनुसार, योजना के तहत देय बेरोजगारी भत्ते और विलंब प्रतिकर के मद में होने वाले व्यय को वहन करेगी।

6—मानक आवंटन का राज्य के भीतर वितरण—राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अनुमोदित मानक आवंटन प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायतों के श्रेणीकरण और ग्राम पंचायत—वार आवंटन तथा सम्बंधित जिला आवंटन निर्धारित करने हेतु आकलित स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिलों और ग्राम पंचायतों में आवंटन का साम्यापूर्ण, आवश्यकता—आधारित और पारदर्शी राज्य के भीतर वितरण सुनिश्चित करेगी; और ऐसे वितरण के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली, मापदंड और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

7—योजना के अधीन मंजूर प्रशासनिक लागतों में से, कम से कम एक—तिहाई का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक और किए गए कार्य के अनुसार अन्य तकनीकी कर्मियों को नियोजित करने व उनके भुगतान हेतु तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए किया जाएगा।

अध्याय — सोलह

पारदर्शिता और सार्वजनिक प्रकटीकरण

48—सक्रिय प्रकटीकरण—

1—अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा और सार्वजनिक संवीक्षा के लिए ग्राम स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2—प्रत्येक कार्यस्थल पर एक “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें कार्य का ब्यौरा, अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री का मात्रा और मद-वार (Item-Wise) लागत प्रदर्शित की जाएगी।

3—प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या, मजदूरी संदाय, सामग्री संदाय, अधिनियम के अधीन गारंटी, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन अनुमोदित कार्य, और ग्राम पंचायत तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष-वार लिए गए या पूर्ण किए गए कार्यों का डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन किया जाएगा।

4—इस योजना के अधीन कार्यों, श्रम की मांग, प्रदान किए गए रोजगार, संदाय, सामग्री के उपयोग और भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण, नामनिर्दिष्ट पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से उत्पन्न किए जाएंगे और सार्वजनिक रूप से सुलभ भौतिक और डिजिटल प्रारूपों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत कार्यों की प्रास्थिति, संदाय, शिकायतों और अन्य सुसंगत जानकारी को समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें बुलाई जायेंगी।

5—जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आधिकारिक वेबसाइटों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में नियमित रूप से अद्यतन किया जाए, जिससे अधिनियम से सम्बंधित सभी जानकारी निःशुल्क, डाउनलोड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो।

6—योजना से संबंधित मस्टर रोल सहित सभी खाते और रिकॉर्ड निःशुल्क सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो उसकी प्रति या उससे सम्बंधित प्रासंगिक उद्धरण (Extracts) प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऐसी प्रतियां या उद्धरण मांग पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

अध्याय—सत्रह

सामाजिक अंकेक्षण

49—सामाजिक अंकेक्षण का संचालन—

1—इस योजना के तहत सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण के अधीन होंगी।

2—सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया, मानक और तौर-तरीके केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होंगे।

3—जब तक ऐसे नियम अधिसूचित नहीं हो जाते, तब तक ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं का अंकेक्षण नियम, 2011’ के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर लागू होंगे।

50—निष्कर्षों का अनुपालन—

1—सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम सभा में रखा जाएगा।

2—सुधारात्मक और वसूली की कार्रवाई बिना किसी देरी के शुरू की जाएगी।

3—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली एम0आई0एस0 में रिकार्ड की जाएगी।

4—योजना के अधीन खर्च की गई रकम के किसी भी दुर्विनियोग की वसूली राज्य में प्रचलित प्रासंगिक राजस्व कानूनों के अधीन की जाएगी।

5—ऐसी वसूलियों का वह भाग जो केन्द्रीय अंश से सम्बंधित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाएगा।

51—वार्षिक रिपोर्टिंग—

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए एक ‘वार्षिक रिपोर्ट’ तैयार करेंगे। ऐसे रिपोर्ट की एक प्रति योजना में विनिर्दिष्ट शुल्क के संदाय पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराई जायेगी।

अध्याय—अठारह

शिकायत निवारण और लोकपाल

52—शिकायत निवारण तंत्र योजना के तहत एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक समाविष्ट होंगे, अर्थातः—

1—वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र, जिसमें प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जब अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

2—प्रत्येक कर्मकार को सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा और वह योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र के उपबंधों के अनुसार निस्तारण हेतु, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

3—किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत सभी शिकायतों के लिए एक दिनांकित पावती जारी करना।

4—स्थल सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जांच और शिकायतों का निस्तारण, शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

5—जांच पूरी होने पर, सम्बंधित प्राधिकारी तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगा, और शिकायत का समाधान पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

6—निर्धारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निस्तारण करने में विफलता को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।

7—जहाँ प्रारंभिक जांच या सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलते हैं, वहां जिला कार्यक्रम समन्वयक, कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए।

8—सम्बंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को जांच के निष्कर्षों और निवारण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में लिखित रूप में, भौतिक या डिजिटल रूप से सूचित करेगा।

9—सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को समीक्षा और अनुश्रवण के लिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखा जाएगा।

10—ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष होगी; कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष होगी और जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष होगी।

11—सभी अपीलें आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जाएंगी।

12—सभी अपीलों का निस्तारण प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

13—वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर हल न होने वाली किसी भी शिकायत को, नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से, स्वतः अगले उच्च स्तर पर अग्रेषित कर दिया जाएगा, और ऐसी वृद्धिशील शिकायतों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरंतर निगरानी की जाएगी।

53—अभिलेखों का अनुरक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली—

ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और ऐसे रीति में तैयार करेगी और अनुरक्षित करेगी या तैयार और अनुरक्षण कराएगी, जैसा कि जारी किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड और पासबुक, परिवार के मुखिया का नाम, आयु और पता और ग्राम पंचायत से पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्यों को विशिष्टियों से युक्त योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

54—लोकपाल—

राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए शिकायतें प्राप्त करने, जांच करने और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पंचाट जारी करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल इस अधिनियम के अधीन नामनिर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवर्तित कार्य करेगा।

अध्याय—उन्नीस

अनुश्रवण, निरीक्षण और मूल्यांकन

55—अनुश्रवण—

1—राज्य सरकार राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी।

2—प्रबंधन सूचना प्रणाली में डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का अनुरक्षण किया जाएगा।

56—निरीक्षण—

प्रत्येक स्तर पर प्रतिवर्ष कार्यों के न्यूनतम विहित प्रतिशत का निरीक्षण किया जाएगा—

(एक) ग्राम पंचायत स्तर पर—वर्ष के दौरान निष्पादित 100% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(दो) ब्लॉक स्तर पर—सम्बंधित ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 60% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(तीन) जिला स्तर पर—सम्बंधित जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 10% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(चार) राज्य स्तर पर—पूरे राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम से कम 2% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

57—मूल्यांकन—

1—परिणामों और प्रभाव का आकलन करने के लिए नियतकालिक स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाएंगे।

2—मापने योग्य परिणामों और वास्तविक समय की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन और कार्य-पूर्णता के बाद परिसंपत्ति के परिणामों की ट्रैकिंग हेतु प्रौद्योगिकी—सक्षम अनुश्रवण अनिवार्य होगा, जो सत्यापित डेटा सिस्टम और स्थानिक प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित होगा। एक व्यापक पारदर्शिता ढांचे के माध्यम से साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रबलित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समवर्ती मूल्यांकन तंत्र निरंतर सतर्कता प्रदान करेगा और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

58—उल्लंघन के लिए दंड और दुर्विनियोग की गई राशि की वसूली—

1—अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दस हजार रुपये तक के दंड का भागी होगा।

2—योजना के अधीन खर्च की गई राशि के किसी भी दुर्विनियोग (या गबन) को सम्बंधित राज्य में लागू रिकवरी (वसूली) से सम्बंधित कानूनों के तहत वसूल किया जाएगा।

3—ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रीय सरकार के हिस्से से सम्बंधित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय — बीस**प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण****59—प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण—**

(1) राज्य सरकार योजना के प्रभावी नियोजन, निष्पादन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और सुदृढीकरण हेतु एक समर्पित योजना तैयार और कार्यान्वित करेगी।

(2) क्षमता निर्माण योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ (Inter-Alia), संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे:

(एक) योजना के अधीन भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कृत्यकारियों का प्रशिक्षण;

(दो) योजना के उपबंधों, पारदर्शिता तंत्रों और सामुदायिक भागीदारी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पहल;

(तीन) प्रबंधन सूचना प्रणाली, जियो-टैगिंग उपकरणों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर डिजिटल साक्षरता और अभिविन्यास;

(चार) अभिलेख रखना, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण और आस्ति अनुरक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं में संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ करना।

(3) यह योजना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष तैयार की जाएगी और इसे योजना के अधीन राज्य प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण ढांचे के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(4) पंचायती राज संस्थाएं ऐसी क्षमता निर्माण पहलों के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी और निर्वाचित प्रतिनिधियों और कृत्यकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी।

(5) इस उपबंध के अधीन वचनबंध क्रियाकलापों पर व्यय अनुज्ञेय प्रशासनिक और क्षमता निर्माण शीर्षों से पूरा किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय— इक्कीस**समापन सूत्र**

यह योजना अधिनियम के उपबंधों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ी जायेगी। किसी भी असंगति की दशा में, अधिनियम के उपबंध ही अभिभावी होंगे।

आज्ञा से,

सौरभ बाबू,

प्रमुख सचिव।

अनुसूची-एक

[धारा 8(3) देखें]

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारण्टी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी योजना की न्यूनतम विशेषताएं

1-अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा अधिसूचित योजना का नाम "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारण्टी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी)" होगा। इस योजना से सम्बंधित सभी दस्तावेजों में "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारण्टी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025" का उल्लेख किया जाएगा।

2-योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों में "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारण्टी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025" का उल्लेख अनिवार्य होगा।

3-योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे-

(क) इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास के ढांचे को 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण (विजन) के साथ संरेखित करना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस दिनों की संवर्धित वैधानिक मजदूरी-रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

(ख) सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना, जो समेकित होकर 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' का निर्माण करते हैं; इसमें जल-सम्बंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका सम्बंधी अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान दिया जाएगा।

(ग) ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी-रोजगार की गारंटी को ध्यान में रखते हुए और कृषि के व्यस्ततम मौसम के दौरान पर्याप्त कृषि-श्रम की उपलब्धता को सुगम बनाना।

(घ) ग्राम पंचायतों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पी0एम0गति0 शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतुष्टि-संचालित योजना, और समग्र सरकारी वितरण को संस्थागत रूप देना, जो भू-स्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिला और राज्य योजना तंत्रों द्वारा संचालित है और ऐसी योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाएगा।

(ङ) एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को आधुनिक बनाना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, रीयल-टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, अग्रसक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और नियोजन, ऑडिट तथा धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सम्मिलित है।

4-योजना के अंतर्गत कार्य-

1- कार्यों का वर्गीकरण यह योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में चिन्हित तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यों पर केंद्रित होगी।

2- कार्यों की श्रेणियाँ-अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में होंगे, जिनके साथ उनका विषयगत केन्द्र बिन्दु तथा अभीष्ट निष्कर्ष भी निर्धारित होंगे:

(अ) श्रेणी-एक: जल सम्बंधी कार्य (जल सुरक्षा हेतु)-

(क) जल सम्बंधी कार्यों का दायरा-इन कार्यों का मुख्य केन्द्र बिन्दु जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, जल स्रोतों की स्थिरता, जल निकायों का पुनर्जीवन, जलागम विकास तथा वनीकरण पर होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरणात्मक कार्य सम्मिलित होंगे:

(एक) नहरों, बाढ़ अथवा जल मोड़ चौनलों, चेक डैम, गली प्लग तथा भूमिगत डायकों का निर्माण।

(दो) तालाबों, पर्कोलेशन टैंकों, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शापट, इंजेक्शन कुओं तथा उनसे सम्बंधित वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण या पुनर्जीवन।

(तीन) सिंचाई हेतु खुले कुएँ, सूक्ष्म सिंचाई नहरें तथा खेतों तक जल वितरण प्रणाली का निर्माण।

(चार) सामुदायिक जलभराव भूमि का पुनरुद्धार।

(पांच) मृदा एवं नमी संरक्षण से जुड़े वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य।

(छः) छतों पर वर्षा जल संचयन तथा अन्य विकेन्द्रीकृत भूजल पुनर्भरण प्रणालियाँ।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित करना।

(ब) श्रेणी—दो: मूल ग्रामीण अवसंरचना—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सम्पर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मूलभूत नागरिक, सामाजिक, शासन एवं सेवा—प्रदाय अवसंरचना सम्मिलित होगी तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों (Illustrative works) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(एक) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, आर—पार जल निकास, संरचनाओं और ग्रामीण सम्पर्क सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन;

(दो) ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्रामीण पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण;

(तीन) विद्यालय अवसंरचना का निर्माण, जिसमें किचन शेड, अतिरिक्त कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ चहारदीवारी एवं खेल मैदान सम्मिलित हैं;

(चार) श्मशान घाट और सामुदायिक अवसंरचना;

(पांच) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियाँ जिसमें स्थिरीकरण तालाब, सामुदायिक शौचालय परिसर और अपशिष्ट पृथक्करण तथा संग्रहण केंद्र सम्मिलित हैं;

(छः) सौर प्रकाश प्रणालियों और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना की स्थापना;

(सात) ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, परिवहन शेड और अन्य सामान्य ग्रामीण सुविधाएँ;

(आठ) केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अधीन अनुमत ग्रामीण आवास कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अधीन अनुज्ञेय कार्य भी सम्मिलित है;

(नौ) जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अधीन किए गए कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण;

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण में, बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सेवा पहुंच और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(स) श्रेणी—तीन आजीविका सम्बंधी अवसंरचना—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं में ऐसी उत्पादक परिसंपत्तियाँ और सुविधाएँ सम्मिलित होंगी जो कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, मूल्य संवर्धन, कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को समृद्ध करें तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं:

(एक) प्रशिक्षण—सह—कौशल विकास केंद्रों और आजीविका गतिविधियों के लिए वर्क शेड का निर्माण;

(दो) ग्रामीण हाट अथवा साप्ताहिक बाजार और अन्य बाजार अवसंरचना;

(तीन) खाद्यान्न भंडारण भवन, कृषि उत्पाद भंडारण संरचनाएँ, कोल्ड स्टोरेज यूनिट और अन्य कृषि मूल्य शृंखला अवसंरचना;

(चार) स्वयं—सहायता समूहों (SHG) और संघ—स्तरीय संस्थाओं के लिए भवन;

(पांच) वर्मी कम्पोस्ट और एन ए डी पी यूनिट सहित कंपोस्ट संरचनाएँ;

(छः) वृक्ष—पशुचारण घास के मैदान का विकास, डेयरी अवसंरचना और पशु, बकरी, सूअर, मुर्गी और अन्य पशुधन का आश्रय;

(सात) मछली सुखाने के प्रांगड समेत मत्स्य पालन सम्बंधी अवसंरचना;

(आठ) पौधशालाओं का विकास और निर्माण सामग्री उत्पादन;

(नौ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित परिचालित और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रतिरूपण को बढ़ावा देने वाले एकीकृत प्रोजेक्ट (परियोजनाएँ)।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: सतत आजीविका, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सुदृढीकरण।

(द) श्रेणी चार—चरम मौसम सम्बंधी घटनाओं का न्यूनीकरण और आपदा—पूर्व तैयारी के लिए विशेष कार्य—

(क) विषयगत प्राथमिकताओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, तथा ग्रामीण समुदायों और परिसंपत्तियों को बाढ़, चक्रवातों, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि और अन्य चरम मौसम की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना सम्मिलित होगा तथा इसके उदाहरणात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं:

(एक) चक्रवात आश्रयों, बाढ़ आश्रयों और बहुउद्देशीय आपदा—प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण;

(दो) जल मोड़ नहरों, तटबंध का निर्माण और अन्य आपदा—न्यूनीकरण कार्य;

(तीन) बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाबों एवं जल संरचनाओं का स्थिरीकरण;

(चार) आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों, पुनर्वास, पुनर्स्थापन तथा मरम्मत;

(पांच) पवन—रोधी और आश्रय—पट्टी वृक्षारोपण;

(छह) अग्नि सहित वनाग्नि प्रबंधन कार्य;

(सात) अवरोधकों, ईंधन बफर क्षेत्र तथा संबंधित उपाय।

(ख) अभीष्ट निष्कर्ष: चरम मौसमीय परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम जलवायु —लचीले ग्रामों का निर्माण।

3—केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य।

4—अधिनियम के अधीन बनाई गई ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

5—व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अधीन आवास सम्बंधी कार्य, स्वच्छता सम्बंधी कार्य और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन संचालित एवं इस योजना में सम्मिलित करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिसूचित अन्य लाभार्थीपरक विकासात्मक कार्य सम्मिलित हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार की संबंधित योजनाओं के अधीन निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी, साथ ही ऐसे समस्त कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मानदंडों, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप होंगे।

6—व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य के लिए लाभार्थी की पात्रता मानदंड—

उपर्युक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तिगत परिसंपत्ति सृजन वाले कार्यों को उन परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या वास स्थान पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो निम्न श्रेणियों से संबंधित हैं:

(एक) अनुसूचित जातियाँ;

(दो) अनुसूचित जनजातियाँ;

(तीन) घुमंतू जनजातियाँ;

(चार) विमुक्त जनजातियाँ;

(पांच) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग;

(छ:) महिला—प्रधान परिवार;

(सात) दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित परिवार;

(आठ) भूमि सुधार के लाभार्थी;

(नौ) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी; और

(दस) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन लाभार्थी और उपर्युक्त श्रेणियों के अधीन पात्र लाभार्थियों के निःशेष होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लघु एवं सीमांत किसानों की भूमि पर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित शर्तों के अध्याधीन कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें यह आवश्यक शर्त भी सम्मिलित है कि ऐसे परिवारों के पास वैध जॉब कार्ड हो तथा उनकी भूमि या वास—स्थान पर किए जाने वाले कार्य में कार्य करने के लिए परिवार का कम से कम एक सदस्य इच्छुक हो।

5-योजना के अंतर्गत सहभागितापूर्ण योजना-

(1) सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाएँ, जिन्हें अभिसरण और संतुष्टि-आधारित योजना के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, को एकीकृत योजना प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाएगा, जो विकास ग्राम पंचायत योजनाओं पर आधारित होगी।

(2) विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित और सहभागी नियोजन अभ्यास किया जाएगा।

विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा जी०आई०एस० आधारित उपकरणों, पी०एम० गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार की जाएंगी और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को अपेक्षित आउटपुट और परिणामों के साथ संबंधित पंचायतों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और सभी ग्राम पंचायतों में पात्र आस्तियों और परिणामों के व्यापक कवरेज के लिए संतुष्टि-आधारित योजना के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके।

विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा।

प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शहरी क्षेत्रों से निकटता सहित विकास मापदंडों के आधार पर निर्धारित अपनी श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' आदि में वर्गीकरण के अनुसार संतुष्टि-मोड योजनाएं तैयार करेगी।

ऐसे सभी कार्य विशेष रूप से 'अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना' से लिए जाएंगे, जिसे पी०एम० गति शक्ति, जी०आई०एस० आधारित उपकरणों और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके तैयार किया गया है।

(4) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में पहचाने गए कार्यों को अभिसरण में विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। ऐसे अभिसरण के लिए ली जाने वाली योजनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

6-अभिसरण और एकीकृत नियोजन के लिए ढांचा-

ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए सभी कार्यों के सुसंगत नियोजन, निष्पादन और अनुश्रवण के लिए एक 'एकीकृत अभिसरण ढांचा' स्थापित किया जाएगा, और इस उद्देश्य के लिए—

(1) अभिसरण और संतुष्टि-आधारित योजना के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं को 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' पर आधारित एक एकीकृत योजना प्रक्रिया के अधीन लाया जाएगा।

(2) सभी विद्यमान परिसंपत्तियां और प्रस्तावित कार्य, चाहे वे इस योजना के अधीन वित्त-पोषित हों या किसी अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजना के माध्यम से, निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके 'विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक' के माध्यम से अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत और ट्रैक किए जाएंगे, जो ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों का एक व्यापक रजिस्टर बनाए रखेगा, कार्यों के दोहराव को रोकेगा, विभागीय निवेशों को एकीकृत करेगा और सभी कार्यों को संतुष्टि परिणामों के साथ संरेखित करेगा।

(3) ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकल डिजिटल बैकबोन उपलब्ध होगा जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से सम्बंधित अवसंरचना और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विशेष कार्य सम्मिलित होंगे;

और सभी नियोजन विकसित ग्राम पंचायत योजना की तैयारी से शुरू होकर एक कठोर 'नीचे से ऊपर की ओर' प्रक्रिया का पालन करेंगे, जिसे ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर क्रमिक रूप से संकलित किया जाएगा, और संकलित राज्य योजना को अनुमोदन के लिए 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' के समक्ष रखा जाएगा।

वार्षिक योजनाएं मानकीय आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(4) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक राज्यों, जिलों और पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिकता वाले अवसंरचना के अंतरालों की पहचान करने, कार्यों के डिजाइनों को मानकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करेगा कि सार्वजनिक निवेश ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर संतुष्टि के परिणामों में मापने योग्य योगदान करेगा।

(5) यह संस्थागत व्यवस्था एकल-योजना, बहु-वित्तपोषण (Single-Plan, Multi-Funding) दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेगी, विभिन्न विभागों एवं योजनाओं के मध्य अभिसरण (Convergence) को प्रोत्साहित करेगी तथा ग्रामीण विकास से सम्बंधित सभी प्रयासों को 'विकसित भारत @2047' के उस दृष्टिकोण के अनुरूप समन्वित करेगी, जिसका उद्देश्य उत्पादक, सुदृढ़ (Resilient) एवं परिवर्तनकारी ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करना है।

(7) राज्य के भीतर मानक आवंटन का वितरण:

राज्य सरकार, केंद्र सरकार से स्वीकृत मानक आवंटन प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि यह आवंटन जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच न्यायसंगत, आवश्यकता-आधारित और पारदर्शी तरीके से वितरित किया जाए। इस वितरण में ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण और स्थानीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत-वार और जिला-वार आवंटन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे वितरण की विस्तृत कार्यप्रणाली, मानदंड और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएँगी।

(8) चल रहे कार्यों का पूर्ण होना:

नए कार्य शुरू करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चल रहे या अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, बशर्ते कि यह योजना मानकों और स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप हो।

(9) कार्यों के लिए तकनीकी अनुमान और मानक:

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कार्य का तकनीकी अनुमान और डिजाइन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह स्वीकृति विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप ढांचे के आधार पर दी जाएगी।

(10) निर्माण से संबंधित कार्यों में, जहाँ तक संभव हो, श्रम-प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जो श्रम की उपलब्धता और स्थानीय सामग्री के उपयोग पर निर्भर होंगी।

(11) कार्यों की मात्रा सूची में स्पष्ट और सामान्य रूप से समझ में आने वाली शब्दावली का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(12) प्रत्येक कार्य के साथ अनुमान, डिजाइन और एक तकनीकी विवरण शामिल होगा, जिसमें अपेक्षित आउटपुट और परिणाम बताए जाएंगे।

(13) सभी तकनीकी अनुमान, डिजाइन और परिणाम सम्बंधी विवरण डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से तैयार या अपलोड किए जाएंगे, जो निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकीकृत होंगे।

(14) प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति:

(एक) ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर समेकित कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार 30 दिनों के भीतर प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(दो) स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि—

(क) प्रस्तावित कार्य केवल स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना से ही लिए जाएँ;

(ख) कार्य विषयगत क्षेत्रों और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप हों;

(ग) सभी स्वीकृत कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही संचालित किए जाएँ।

15—मस्टर रोल और उपस्थिति प्रणाली—

इस योजना के अधीन किए गए कार्यों के लिए मस्टर रोल डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से अनुरक्षित किए जाएंगे और निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे—

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में होगा और इसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट पहचान संख्या (ई-मस्टर) होगी। मस्टर रोल में उन सभी श्रमिकों के नाम सम्मिलित होंगे, जिन्होंने काम की मांग की है या जिन्हें काम आवंटित किया गया है और इसे ग्राम पंचायत के प्राधिकृत पदाधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(ख) कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके दैनिक रूप से दर्ज की जाएगी, और समस्त उपस्थिति विवरण दैनिक आधार पर नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक रूप से देखने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) ई-मस्टर रोलों का प्रसंस्करण सम्बंधित दिशा-निर्देशों में विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

16-कार्य का मापन-

1-मजदूरी संदाय केवल कार्यस्थल पर अधिकृत तकनीकी कार्मिकों द्वारा मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर किए गए मापन के आधार पर किया जाएगा, और इसे निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल रूप से अभिलेखित किया जाएगा।

2-राज्य सरकार समय पर मापन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी कार्मिकों का अभिनियोजन सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त व्यक्तियों को प्रत्यायोजित तकनीकी जिम्मेदारियों के साथ, प्रशिक्षित किया जायेगा और अभिनियोजित किया जाएगा, तथा उन्हें कुशल दरों पर मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

17- आउटपुट (उत्पादन) के साथ मजदूरी का जुड़ाव और दर अनुसूची-

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के मजदूरी को पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा से जोड़ा जाए तथा उसका निर्धारण विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न मौसमों के लिए 'समय-और-गति अध्ययन' के आधार पर अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित 'ग्रामीण दर अनुसूची' के अनुसार होगा।

18- कमजोर समूहों के लिए दर की विशेष अनुसूची-

महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्बल करने वाली बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के कार्यों में उनकी उत्पादक सहभागिता को सुकर बनाने हेतु एक अलग 'दर की अनुसूची' को अंतिम रूप दिया जाएगा।

19- कार्य के घंटे और उपार्जन मानक-

1-दर की अनुसूची इस प्रकार विरचित की जाएगी कि आठ घंटे कार्य करने वाला एक वयस्क व्यक्ति, जिसमें एक घंटे का विश्राम सम्मिलित हो अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य रकम उपार्जित कर सके।

2-एक वयस्क श्रमिक के कार्य के घंटे लचीले (Flexible) हो सकते हैं, लेकिन वे विश्राम के अन्तरालों सहित एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तारित नहीं होंगे।

20- सामग्री घटक-

इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों में सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21- ठेकेदारों के बिना निष्पादन-

1-इस अधिनियम के अधीन व्यय के माध्यम से वित्तपोषित किसी भी कार्य या उसके घटक के निष्पादन के लिए किसी भी ठेकेदार को नियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्य योजना के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्षतः निष्पादित किए जाएंगे, जिसमें अनिवार्य स्वतः प्रकटीकरण और सामाजिक अंकक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है।

2-अभिसरण के मामलों में, जहाँ किसी कार्य के घटकों को अन्य योजनाओं के अधीन वित्तपोषित किया जाता है, उन घटकों का निष्पादन अभिसरण करने वाली योजना के मानकों के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें अनुज्ञा प्राप्त होने पर ठेकेदारों का उपयोग भी सम्मिलित है।

22—श्रम-आधारित कार्य प्रणाली—

जहाँ तक हो सके यथासाध्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके किए जाएंगे और ऐसी किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा जो श्रम को विस्थापित करती हो।

23—सामग्रियों का पारदर्शी उपापन —

कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का उपापन ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पारदर्शी उपापन प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई-निविदा प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी।

24—प्रशासनिक लागत का उपयोग—

योजना के अधीन मंजूर प्रशासनिक लागतों में से, कम से कम एक—तिहाई का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक और किए गए कार्य के अनुसार अन्य तकनीकी कर्मियों को नियोजित करने व उनके भुगतान हेतु तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए किया जाएगा।

25—पारदर्शिता और जवाबदेही—

(एक) इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की जाने वाली प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रावधान शामिल होंगे। इनमें अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामाजिक अंकक्षण शामिल होंगे।

(दो) सक्रिय प्रकटीकरण—

1—अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण, नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा और सार्वजनिक संवीक्षा के लिए ग्राम स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2—प्रत्येक कार्यस्थल पर एक “जनता बोर्ड” प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें कार्य का ब्यौरा, अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्रा और मद-वार (Item-Wise) लागत प्रदर्शित की जाएगी।

3—प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या, मजदूरी संदाय, सामग्री संदाय, अधिनियम के अधीन गारंटी, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन अनुमोदित कार्य, और ग्राम पंचायत तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष-वार लिए गए या पूर्ण किए गए कार्यों का डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन किया जाएगा।

4—इस योजना के अधीन कार्यों, श्रम की मांग, प्रदान किए गए रोजगार, संदाय, सामग्री के उपयोग और भौतिक प्रगति से सम्बंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण, नामनिर्दिष्ट पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से उत्पन्न किए जाएंगे और सार्वजनिक रूप से सुलभ भौतिक और डिजिटल प्रारूपों में प्रदर्शित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत कार्यों की प्रास्थिति, संदाय, शिकायतों और अन्य सुसंगत जानकारी को समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें बुलाई जायेंगी।

5—जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आधिकारिक वेबसाइटों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2005) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में नियमित रूप से अद्यतन किया जाए, जिससे अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी निःशुल्क, डाउनलोड करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो।

(तीन) सामाजिक अंकक्षण—

1—इस योजना के तहत सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार सामाजिक अंकक्षण के अधीन होंगी।

2—सामाजिक अंकक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया, मानक और तौर-तरीके केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होंगे।

3-जब तक ऐसे नियम अधिसूचित नहीं हो जाते, तब तक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं का अंकेक्षण नियम, 2011' के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर लागू होंगे।

(चार) समकालीन मूल्यांकन तंत्र -

परिणामों को मापने योग्य बनाने और वास्तविक समय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक-आधारित निगरानी अनिवार्य होगी। इसमें कार्य निष्पादन और कार्य पूर्ण होने के बाद परिसंपत्ति के परिणामों की ट्रैकिंग की जाएगी, जो सत्यापित डेटा प्रणाली और स्थानिक तकनीकों पर आधारित होगी। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को एक व्यापक पारदर्शिता ढांचे के माध्यम से और मजबूत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक समकालीन मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाएगा, जो निरंतर निगरानी सुनिश्चित करेगा और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाएगा।

26-धन की वसूली-

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत व्यय की गई किसी भी राशि का दुरुपयोग होने पर उसकी वसूली सम्बंधित राज्य में लागू राजस्व कानूनों के अनुसार की जाएगी।

(ख) वसूली की गई राशि में से केंद्र सरकार के हिस्से को भारत की संचित निधि में, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से जमा किया जाएगा।

(दो) वसूली गई राशि में से केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित भाग को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

27-निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण-

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नामित गुणवत्ता-नियंत्रण टीमों द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाए, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं, माप की सटीकता सही है, और मजदूरी का भुगतान वास्तव में किए गए कार्य की मात्रा के अनुरूप है। सभी निरीक्षण रिपोर्टें प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड की जाएंगी।

28-शिकायत निवारण तंत्र-

शिकायत निवारण तंत्र योजना के तहत एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक समाविष्ट होंगे, अर्थात:-

1-वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र, जिसमें प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक दिन नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जब अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहेंगे;

2-प्रत्येक कर्मकार को सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा और वह योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र के उपबंधों के अनुसार निस्तारण हेतु, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा;

3-किसी भी प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत सभी शिकायतों के लिए एक दिनांकित पावती जारी करना;

4-स्थल सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जांच और शिकायतों का निस्तारण, शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण किया जाएगा;

5-जांच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगा, और शिकायत का समाधान पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा;

6-निर्धारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निस्तारण करने में विफलता को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा;

7-जहाँ प्रारंभिक जांच या सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलते हैं, वहां जिला कार्यक्रम समन्वयक, कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए;

8-सम्बंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को जांच के निष्कर्षों और निवारण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में लिखित रूप में, भौतिक या डिजिटल रूप से सूचित करेगा;

9—सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को समीक्षा और अनुश्रवण के लिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखा जाएगा;

10—ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष होगी; कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष होगी; और जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के समक्ष होगी।

11—सभी अपीलों आदेश की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर दाखिल की जाएंगी;

12—सभी अपीलों का निस्तारण प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा;

13—वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर हल न होने वाली किसी भी शिकायत को, नामनिर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से, स्वतः अगले उच्च स्तर पर अग्रेषित कर दिया जाएगा, और ऐसी वृद्धिशील शिकायतों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरंतर निगरानी की जाएगी।

29—लोकपाल—

राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए शिकायतें प्राप्त करने, जांच करने और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पंचाट जारी करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल इस अधिनियम के अधीन नामनिर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रवर्तित कार्य करेगा।

30—उल्लंघन पर कार्रवाई—

जब भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा उचित जांच के बाद हो जाती है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, लोकपाल या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा धारा 27 या संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

31—वार्षिक रिपोर्ट—

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट की एक प्रति जनता को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए योजना में निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है।

32—योजना से संबंधित सभी खाते और अभिलेख, जिनमें मास्टर रोल भी शामिल हैं, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन देने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर संबंधित प्रतियाँ या आवश्यक अंश प्राप्त कर सकेगा।

33—क्षमता निर्माण और पंचायत सशक्तिकरण—

ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए एक समर्पित योजना बनाई जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण, सूचना—शिक्षा—संचार, डिजिटल साक्षरता तथा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उपाय शामिल होंगे।

अनुसूची—दो

1—ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड—

1—परिवार रजिस्ट्रीकरण— ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक है, रजिस्ट्रीकरण और 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी करने के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वे रहते हैं, में अपने परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पता प्रस्तुत कर सकता है।

2—विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, जहाँ रोजगार इच्छुक निम्नलिखित में से है —

- (क) एकल महिला; या
- (ख) दिव्यांग व्यक्ति; या
- (ग) साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति; या
- (घ) एक मुक्त बंधित श्रमिक; या
- (ङ) विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह से सम्बंधित व्यक्ति; या
- (च) ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

3—एक अलग रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन और कार्यस्थल की सुविधाओं, जैसा लागू हो, में विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

4—यह ग्राम पंचायत का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा कि उपयुक्त समझे, ऐसा आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करे, जिसमें एक परिवार के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों का विवरण, उनके फोटो, बैंक या डाकघर खाता संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और आधार संख्या, यदि कोई हो सहित अद्वितीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य संख्या अंतर्विष्ट हो।

5—जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड तीन साल के लिए वैध होगा, जिसके पश्चात उचित सत्यापन के उपरान्त इसका नवीकरण किया जा सकता है।

6—कोई भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार के सिवाय रद्द नहीं किया जाएगा—

(एक) जहाँ यह द्विप्रतिक पाया जाता है;

(दो) जहाँ पूरा परिवार स्थायी रूप से ग्राम पंचायत की अधिकारिता से बाहर प्रव्रजन कर गया हो, और अब गांव में नहीं रहता हो; या

(तीन) जहाँ रजिस्ट्रीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो गई हो।

7—राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में नियमित रूप से निम्नलिखित विवरणों को योजना के अधीन निम्नानुसार मुख्य गारंटियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अद्यतन करने की व्यवस्था करेगी:—

(एक) उन दिनों की संख्या जिनके लिए कार्य की मांग की गई थी;

(दो) आवंटित कार्य के दिनों की संख्या;

(तीन) मस्टर रोल संख्या सहित आवंटित कार्य का विवरण;

(चार) माप का विवरण;

(पांच) भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता, यदि कोई हो;

(छह) भुगतान की गई मजदूरी की दिनांक-वार राशि;

(सात) भुगतान किया गया विलंब प्रतिकर, यदि कोई हो;

(आठ) प्रदान की गई परिसंपत्ति, यदि कोई हो।

2—कार्य की मांग—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज है, योजना के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और ऐसे प्रत्येक आवेदन का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, तथा दिनांक सहित जारी रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिये गये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा।

(दो) राज्य सरकार समूहों की आवश्यकताओं की सक्रिय जांच करेगी और उन्हें कार्य प्रदान करेगी।

(तीन) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है और यह आवेदन वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी भी माध्यम से किया जा सकता है।

(चार) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में एक साथ दिया जा सकता है।

(पांच) किसी व्यक्ति द्वारा आवेदित रोजगार के दिनों की संख्या या उसे वास्तव में दिए गए रोजगार के दिनों की संख्या पर परिवार की कुल गारंटी के अधधीन कोई सीमा नहीं होगी।

(छः) सामान्यतः कार्य के लिए आवेदन न्यूनतम 6 दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए।

(सात) योजना में अग्रिम आवेदन की व्यवस्था होगी, अर्थात् जिस दिनांक से रोजगार चाहिए उससे पहले भी आवेदन दिया जा सकता है।

(आठ) एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन जमा करने का योजना में उपबंध किया जाएगा, परन्तु यह कि वे अवधियां जिनके लिए रोजगार मांगा गया है, आपस में अतिव्यापी न हों।

3—कार्य का आवंटन—

1—ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदक को योजना के उपबंधों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के दिनांक या अग्रिम आवेदन की स्थिति में जिस दिनांक से कार्य चाहा गया हो, जो भी बाद में हो, से 15 दिन के अंदर अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा।

2-महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी कि रजिस्ट्रीकृत और कार्य मांगने वाली लाभार्थियों में न्यूनतम एक-तिहाई महिला लाभार्थी हों। एकल महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

3-आवेदक, जिन्हें कार्य प्रदान किया गया है, उनको लिखित रूप में सूचना ग्राम रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए पते पर उन्हें प्रेषित पत्र के माध्यम से या किसी अन्य प्रभावी संचार माध्यम से या जिला, मध्यवर्ती या ग्राम पंचायत के कार्यालय में सार्वजनिक नोटिस लगाकर दी जायेगी।

4-जिन व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है, उनकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे और यह सूची राज्य सरकार तथा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

5-यथासम्भव, आवेदन के समय आवेदक के निवास वाले गांव से 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर ही रोजगार प्रदान किया जाएगा।

6-योजना के अधीन नया कार्य तब शुरू किया जा सकता है जब न्यूनतम 10 श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हों, परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित, पहाड़ी क्षेत्रों में और वृक्षारोपण सम्बंधी कार्यों के सम्बंध में नये कार्यों में यह शर्त लागू नहीं होगी।

7-यदि 5 किलोमीटर की त्रिज्या से बाहर कार्य प्रदान किया जाता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और रहने-खाने के खर्च के लिए मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जायेगा।

8-रोजगार की अवधि एक सप्ताह में छह दिन से अधिक न होने के साथ न्यूनतम छह दिन निरंतर होगी।

4-कार्यस्थल प्रबंधन-

1- कार्यस्थल पर पारदर्शिता के प्रयोजन से, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा-

(एक) एक परियोजना प्रारंभ बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें श्रमिकों को कार्य के विभिन्न उपबंधों के बारे में समझाया जाएगा;

(दो) मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी;

(तीन) प्रत्येक कार्य का मापन अभिलेख और श्रमिकों का ब्यौरा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा;

(चार) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक 'नागरिक सूचना बोर्ड' लगाया जाएगा और इसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा; और

(पांच) केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति सभी कार्यों की जाँच कर सकती है और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में 'कार्य रजिस्टर' में दर्ज की जाएगी और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी।

2-कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया और विश्राम की अवधि, मामूली चोटों और किए जा रहे कार्य से संबंधित अन्य स्वास्थ्य खतरों के आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

3-यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ आने वाले पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक है, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन्हीं महिला श्रमिकों में से एक को प्रतिनियुक्त करने का उपबंध किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर का संदाय किया जाएगा।

5- कल्याण-

1-यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजन के दौरान और उससे सम्बंधित किसी दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो वह आवश्यकतानुसार निःशुल्क चिकित्सा उपचार का हकदार होगा।

2-जहाँ घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो वहाँ राज्य सरकार आवास, उपचार, दवाओं और दैनिक भत्ते जो मजदूरी दर के आधे से कम न हो के संदाय सहित ऐसे चिकित्सालय में भर्ती की व्यवस्था करेगी।

3-यदि योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे या उसके कानूनी वारिसों को यथास्थिति कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अधीन हकदारी के अनुसार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुग्रह राशि का संदाय किया जाएगा।

4— यदि योजना के अधीन नियोजित व्यक्तित्व के साथ आए किसी बच्चे को दुर्घटना से कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा उपचार का हकदार होगा; और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में, राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित कानूनी संरक्षकों को अनुग्रह राशि का संदाय किया जाएगा।

6—विलम्ब प्रतिकर—

(1) यदि मस्टर रोल बंद होने के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तो मजदूरी मांगने वाले मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के पश्चात, विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए, असंदत्त मजदूरी का 0.05% प्रतिकर पाने के हकदार होंगे।

(2) प्रतिकर के संदाय में संदेय के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक का विलंब मजदूरी के संदाय में विलंब के समान ही माना जाएगा।

(3) मजदूरी संदाय में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभिन्न कृत्यकारियों या अभिकरणों की जिम्मेदारी तय करने के प्रयोजन से, राज्य मजदूरी के निर्धारण और संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित करेंगे, जैसे—

(एक) कार्य का मापन;

(दो) मस्टर रोल का कंप्यूटरीकरण;

(तीन) मापन का कंप्यूटरीकरण;

(चार) मजदूरी सूची तैयार करना; और

(पांच) निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) को अपलोड करना; और

विनिर्दिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए जिम्मेदार कृत्यकारियों या अभिकरणों के साथ चरण-वार अधिकतम समय सीमा विनिर्दिष्ट करेंगे।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में मस्टर रोल के बंद होने के दिनांक और मजदूरी मांगने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने के दिनांक के आधार पर संदेय प्रतिकर की स्वचालित गणना का उपबंध होगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सम्यक सत्यापन के बाद अग्रिम रूप से प्रतिकर मुआवजे का संदाय करेंगे और संदाय में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कृत्यकारियों या अभिकरणों से प्रतिकर की धनराशि की वसूली करेंगे।

(6) विलंब के दिनों की संख्या, संदेय प्रतिकर और वास्तविक संदाय प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) अधिनियम की धारा 29 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

7—मजदूरी का संदाय, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, संबंधित बैंकों या डाकघरों में कर्मचारों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

8—योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार में केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 25, 1976) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9—अभिलेखों का अनुरक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली—

ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और ऐसे रीति में तैयार करेगी और अनुरक्षित करेगी या तैयार और अनुरक्षण कराएगी, जैसा कि जारी किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड और पासबुक, परिवार के मुखिया का नाम, आयु और पता और ग्राम पंचायत से पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्यों को विशिष्टियों से युक्त योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

10—(1) इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप जैसी किसी भी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यः—

(एक) अस्थायी पुनःस्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण और 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी करने की मांग कर सकते हैं;

(दो) अस्थायी पुनःस्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं; और

(तीन) कार्ड के खो जाने या नष्ट होने की स्थिति में पुनः रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का विवरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित किया जाएगा।

(3) सामान्य स्थिति बहाल होने पर, इस प्रकार जारी किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को मूल निवास स्थान पर पुनः पृष्ठांकित किया जाएगा और मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त होने पर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा।

11—शिकायत निवारण का अधिकार—

प्रत्येक श्रमिक को सुनवाई किये जाने का और योजना के अधीन शिकायत निवारण तंत्र के उपबंधों के अनुसार निपटान हेतु, कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप में अपनी शिकायत रजिस्टर कराने का अवसर होगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. DFA/1517518 /XXXVIII-6003(001)/1-2026, dated June 29, 2026 :

No. DFA/1517518 /XXXVIII-6003(001)/1-2026

Dated Lucknow, June 29, 2026

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB-G RAM G Act, 2025 (Act no. 36 of 2025), the State Government hereby notifies the following Scheme, namely:-

VIKSIT BHARAT - GUARANTEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GRAMIN)

(VB-G RAM G) SCHEME, UTTAR PRADESH

CHAPTER- I

SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND DEFINITIONS

1. Short title and commencement-

1. This Scheme may be called the "Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Scheme, Uttar Pradesh".
2. It shall come into force on July 1, 2026.
3. This Scheme shall apply to all notified rural areas of the State.

2. Definitions-

Unless the context otherwise requires, all terms used herein shall have the meanings assigned to them in Section -2 of the Act.

- (a) "Adult" means a person who has completed the eighteenth year of age;
- (b) "Applicant" means the head of a household or any of its other adult members who has applied for employment under the Scheme;
- (c) "Block" means a community development area within a district comprising a group of Gram Panchayats;
- (d) "Centrally Sponsored Scheme" means a scheme in which the Central Government provides full or partial financial assistance and the State Governments undertake its implementation;
- (e) "District Programme Coordinator" means an officer of the State Government designated as such officer under sub-section (1) of Section 17 for the implementation of the Scheme in a district;
- (f) "Household" means the members of a family related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals or holding a common ration card;
- (g) "Implementing Agency" includes any department of the Central Government or a State Government, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or the Government undertaking, to undertake the implementation of any work taken up under the Scheme;

- (h) "Intermediate Level" means a level between the village and district levels as specified under clause (c) of article-243 to the Constitution of India;
- (i) "National Level Steering Committee" means a steering committee constituted by the Central Government under sub-section (1) of Section 14;
- (j) "Normative Allocation" means the allocation of the fund made by the Central Government to the State;
- (k) "Notification" means a notification published in the Official *Gazette* and the term "Notify" or "Notified", shall be construed accordingly;
- (l) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of Section 18;
- (m) "Rural Area" means any area in a State except those areas covered by any urban local body or a Cantonment Board established or constituted under any law for the time being in force;
- (n) "Schedule" means Schedules appended to this Act;
- (o) "Scheme" means the Scheme notified by the State Government under sub-section (1) of Section 3;
- (p) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union territory;
- (q) "State Council" means the State Gramin Rozgar Guarantee Council constituted under sub-section (1) of Section 13;
- (r) "State Level Steering Committee" means a steering committee constituted under sub-section (1) of Section 15;
- (s) "Unskilled manual work" means any physical work which any adult person is capable of doing without any skill or special training;
- (t) "Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack" means the consolidated aggregation comprising proposed works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans aggregated at the District and State levels, and aligned with the four thematic domains of works specified in Schedule- I;
- (u) "Viksit Gram Panchayat Plan" means a future-ready, convergence- based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047, formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence-based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of works under this Act, as provided in sub-section (3) of Section 4;
- (v) "Wage Rate" means the wage rate referred to in Section 10;
- (w) "Work" means any work undertaken or executed under the Scheme.

CHAPTER- II

OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES

3. Objectives-

(a) The primary objective of this Scheme is to align the rural development framework with the national vision of Viksit Bharat @2047 by providing an enhanced statutory wage- employment guarantee of one hundred and twenty-five days in each financial year to such rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to participate more effectively in the expanded livelihood security framework.

(b) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through public works aggregating into forming Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security through water-related works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and special works to mitigate extreme weather events.

(c) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons, and, in view of the wage-employment guarantee for the rural workforce.

(d) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole of government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with the PM Gati Shakti to address the varying needs of Gram Panchayats, powered by geospatial systems, digital public infrastructure, district and State planning mechanisms, with such plans aggregated at the Block, District, State and National levels.

(e) To modernise governance, accountability and citizen engagement through a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication at various levels, global positioning system or mobile based worksite monitoring, real time management information system dashboards, proactive public disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud risk mitigation.

CHAPTER- III

GUARANTEES, TIME LIMITS AND CONDITIONS

4. Guarantee-

(a) State Government shall, in such rural area in the Uttar Pradesh as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than one hundred and twenty-five days of guaranteed employment in a financial year in accordance with the Scheme.

(b) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.

(c) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(d) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of this section.

(e) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

5. Conditions for demand-

(1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

CHAPTER- IV

PLANNING FRAMEWORK

6. Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP)-

(1) A future-ready, convergence based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047, formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence-based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of works under this Scheme.

(2) There shall be a systematic and participatory planning exercise undertaken at each tier of the Panchayati Raj system in accordance with the specified methodology.

The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by the Gram Panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval.

Works proposed to be undertaken by the Intermediate Panchayat, District Panchayat or other implementing agencies shall likewise be placed before the respective Panchayats along with the expected outputs and outcomes.

The Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural development strategies, and saturation-based planning for comprehensive coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats.

All works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the Viksit Bharat-National Rural Infrastructure Stack.

(3) Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its classification into Category A, B, C, *etc.*, determined based on development parameters, including proximity to urban areas, to address the varying needs of the Panchayats.

All such works shall be drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan, prepared using PM Gati Shakti, GIS-based tools and other digital public infrastructure.

(4) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

(5) The works identified in the Viksit Gram Panchayat Plans shall be executed through various Central, State and local schemes in convergence.

The schemes to be taken up for such convergence shall be notified by the Central Government.

(6) While preparing Viksit Gram Panchayat Plans and annual labour demand, no work shall be proposed for execution during notified peak agricultural periods.

7. Framework for Convergence and Integrated Planning-

A Unified Convergence Framework shall be established for coherent planning, execution and monitoring of all works undertaken in rural areas, and for this purpose -

(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central Government for the purpose of convergence and saturation-based planning, shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(2) All existing assets and proposed works, whether funded under this Scheme or through any other Central, State or local scheme, shall be mandatorily registered and tracked through the Viksit Bharat-National Rural Infrastructure Stack using the designated digital portal, which shall maintain a comprehensive register of rural public works, prevent duplication, integrate departmental investments, and align all works with saturation outcomes.

(3) Single digital backbone for rural public works covering water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events;

and all planning shall follow a strict bottom-up process beginning with the preparation of the Viksit Gram Panchayat Plan, which shall be successively aggregated at the Block, District and State levels, and the aggregated State Plan shall be placed before the State Level Steering Committee for approval.

Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

(4) Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States, Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments contribute measurably to saturation outcomes at the Gram Panchayat, Block and District levels.

(5) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding approach, promote convergence across departments and schemes, and align all rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision of creating productive, resilient and transformative rural assets.

CHAPTER- V

STATE INSTITUTIONAL ARCHITECTURE

8. State Gramin Rozgar Guarantee Council-

(1) At the state level, there shall be a State Gramin Rozgar Guarantee Council, which shall be called the "Uttar Pradesh State Gramin Rozgar Guarantee Council".

The Uttar Pradesh State Gramin Rozgar Guarantee Council shall have a state-level General Assembly, which shall consist of the following office bearers/members:

1	Chief Minister, Government of Uttar Pradesh	Chairperson
2	Minister, Rural Development, Uttar Pradesh	Vice-Chairperson
3	Ministers of Finance, Revenue, Forest, Irrigation and Water Resources, Public Works, Agriculture, Planning, Panchayati Raj, Law, Namami Gange and Rural water supply, Rural Engineering, Animal and Husbandry, Horticulture, Fisheries, Co-operative, Social Welfare, Labour	Member
4	Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh	Member
5	Secretary/Principal Secretary/ Additional Chief Secretary of Rural Development, Finance, Revenue, Forest, Irrigation and Water Resources, Public Works, Agriculture, Planning, Panchayati Raj, Law, Namami Gange and Rural water supply, Rural Engineering, Animal and Husbandry, Horticulture, Fisheries, Co-operative, Social Welfare, Labour, Legislative Affairs Departments and others Government of Uttar Pradesh	Member
6	Commissioner, Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Scheme Uttar Pradesh	Member Secretary
7	At least 15 non-official members nominated by the State Government, representatives of Panchayati Raj Institutions, representatives of non-governmental organizations and weaker sections of the society.	Member

Provided that not less than one third of the non-official members nominated under this sub-section shall be woman:

Provided further that not less than one third of the non-official members shall belongs to the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the other backward classes and minorities.

(2) The terms and conditions subject to which the Chairperson and members of the State Council may be appointed and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Council shall be notified as Rule separately.

(3) The duties and functions of the Uttar Pradesh State Gramin Rozgar Guarantee Council:

(i) Advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;

(ii) Reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;

(iii) Monitoring the implementation of Act and the Scheme in the State and coordinating such implementation with the Central Council;

(iv) Preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government;

(v) Any other duty or function as may be assigned to it by the Central Council or the State Government.

(4) The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Scheme operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Scheme and Programmes in the State.

9. State Level Steering Committee-

(1) At the State Level, there shall be a State Level Steering Committee, to provide operational guidance, coordination, and monitor the implementation of the Scheme.

1	Chief Secretary of the State or by an officer not below the rank of Additional Chief Secretary nominated by the State Government	Chairperson
2	Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of the Rural Development Department;	Member
3	Commissioner, Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Scheme Uttar Pradesh	Member Secretary
4	Secretary/Principal Secretary/ Additional Chief Secretary of Finance, Revenue, Forest, Irrigation and Water Resources, Public Works, Agriculture, Planning, Panchayati Raj, Law, Namami Gange and Rural water supply, Rural Engineering, Animal and Husbandry, Horticulture, Fisheries, Co-operative, Social Welfare, Labour, Legislative Affairs and others Departments of Government of Uttar Pradesh	Member
5	Such number of subject-matter experts, as may be determined by the State Government	Member
6	Representatives of technical or research institutions	Member
7	One member nominated by the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India	Member

(3) The State Level Steering Committee shall-

- (i) Oversee State wide planning and convergence with other programmes;
- (ii) Review of district performance and ensure timely preparation of the aggregate State plan;
- (iii) Coordinate with the National Level Steering Committee and implement directions issued therefrom;
- (iv) Support digital systems, monitoring arrangements, and process improvements at the State level; and
- (v) Perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

10. Intermediate Panchayats-

1. The Panchayats at the district, intermediate and village levels shall be the principal authorities for planning, implementation and monitoring of the Scheme made under this Act.

2. The Panchayat at the district level, shall oversee and coordinate implementation of the Scheme in the district, including finalisation and approval of the aggregate district level plan, supervision and monitoring of works, ensuring convergence, and perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

3. The Panchayat at the intermediate level, shall prepare and finalise the aggregate Block level plan, support Gram Panchayats in planning and implementation, supervise works at Gram Panchayat and Block levels, and facilitate convergence with line departments.

4. Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

5. The Gram Panchayat shall register households, receive and process applications for work, prepare the Viksit Gram Panchayat Plans, execute the works assigned to it, maintain such records as may be specified by the State Government, and discharge such other responsibilities as may be entrusted to it under the Scheme.

11. District Programme Coordinator (DPC)-

1. District Collector shall be designated as the District Programme Coordinator for the implementation of the Scheme in the district.

2. The District Programme Coordinator shall be responsible for the implementation of the Scheme in the district in accordance with the provisions of this Scheme and the rules made thereunder.

3. The functions of the District Programme Coordinator shall be as follows, namely: -

(i) The District Programme Coordinator shall be responsible for the consolidation and finalisation of the district aggregate plan and shall oversee convergence, implementation and monitoring of the Scheme at the district level in accordance with the provisions of this Act;

(ii) The District Programme Coordinator shall ensure compliance with the provisions of this Scheme and with the directions and guidelines issued by the Central Government and the State Government, and shall accord such administrative sanctions and clearances as may be required for the timely and effective implementation of the Scheme, including those relating to digital, geospatial and monitoring systems;

(iii) The District Programme Coordinator shall coordinate with Programme Officers, and shall review, monitor and supervise their performance using the monitoring framework, management information system and accountability mechanisms established under Act and the Scheme;

(iv) The District Programme Coordinator shall conduct periodic inspections of works undertaken under the Scheme, ensure adherence to quality and productivity standards, and shall redress the grievances of applicants through digital public infrastructure and designated grievance redressal systems issued/notified by the Central Government.

4. The District Programme Coordinator, shall prepare an aggregate plan for the district under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated Block Plans and the proposals received from the Zila Panchayats.

12. Programme Officer (Block Level)-

1. At every Panchayat at intermediate level, Block Development shall designated as Programme Officer at the panchayat at intermediate level.

2. The Programme Officer shall assist the Panchayat at the intermediate level in discharging its functions under Act and the Scheme made thereunder.

3. The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from works in the area under his jurisdiction.

4. The Programme Officer shall prepare an aggregate plan for the Block under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and the proposals received from intermediate panchayats.

5. Without prejudice to the generality of sub-section (2), the functions of the Programme Officer shall include-

(i) Monitoring all works and projects undertaken by the Gram Panchayats and other implementing agencies within the Block, ensuring alignment with the Viksit Gram Panchayat Plans;

(ii) Sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to eligible households in accordance with the provisions of this Act;

(iii) Ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under the Scheme within the Block, including through digital and biometric authenticated payment systems, as may be specified by the Central Government;

(iv) Ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of each Gram Panchayat are conducted by the Gram Sabha, and that timely and appropriate action is taken on objections and findings arising from such audits;

(v) Dealing promptly with all complaints and grievances relating to the implementation of the Scheme within the Block, through the grievance redressal mechanisms established under sub-section (1) of Section 25 of this Act;

- (vi) Ensuring the geo-tagging, digital recording, and management information system reporting of all works undertaken within the Block, and compliance with monitoring, productivity, and transparency framework, specified by the Central Government under this Act;
- (vii) Facilitating inter-departmental convergence at the Block level to support saturation-driven planning and the execution of works under the Scheme;
- (viii) Any other function as may be assigned to him by the District
- (ix) Programme Coordinator and the State Government under this Act.

6. The Programme Officer shall perform his function under the direction, control and superintendence of the District Programme Coordinator.

13. Responsibilities of Gram Panchayat–

The Gram Panchayat shall be responsible for -

- (i) Registration of households and issuance of Gramin Rozgar Guarantee Cards;
- (ii) Receiving work applications and maintaining records of Gramin Rozgar Guarantee Cards;
- (iii) Preparing the Viksit Gram Panchayat Plans;
- (iv) Every Gram Panchayat shall, after considering the recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabha, keeping in view of the demand for works, prepare a Viksit Gram Panchayat Plan on saturation basis;
- (v) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.
- (vi) The Programme Officer shall allocate at least fifty per cent. of the works in terms of its cost under the Scheme to be implemented through the Gram Panchayats;
- (vii) The Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with
- (viii) The muster rolls for the works sanctioned to be executed by it;
- (ix) A list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat;
- (x) The Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work;
- (xi) The works taken up by a Gram Panchayat under the Scheme, shall meet the required technical standards and measurements;
- (xii) Executing works allotted to it by the Programme Officer; and
- (xiii) A Gram Panchayat may take up any work under the Scheme from Viksit Gram Panchayat Plan within the area of the Gram Panchayat, as may be sanctioned by the Programme Officer.

14. Social Audit by Gram Sabha–

1. The Gram Sabha, shall monitor and review the execution of all works undertaken under the Scheme within the jurisdiction of the Gram Panchayat, in accordance with the provisions of this Act.
2. The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all works taken up under the Scheme within the Gram Panchayat, as issued/notified by the Central Government.
3. The Gram Panchayat shall make available to the Gram Sabha all records and documents required for conduct of the social audit, including muster rolls, bills, vouchers, measurement books, sanction orders, digital records, geo-tagged photographs, and all other connected books of account and papers, whether maintained in physical or electronic form.

CHAPTER- VI

REGISTRATION AND ROZGAR GUARANTEE CARD

15. Registration of households–

1. Household Registration-The adult member of every household residing in any rural area and willing to undertake unskilled manual work, may submit the names, ages and address of the household to the Gram Panchayat within whose jurisdiction they reside, for the purpose of registration of the household and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card.

2. Special Gramin Rozgar Guarantee Card, where the job seeker is –

- (a) A single woman; or
- (b) A person with disability; or
- (c) Persons above sixty years of age; or
- (d) A released bonded labourer; or
- (e) A person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group; or
- (f) A transgender person.

3. The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour, shall ensure special protection in the providing work, work evaluation, and worksite facilities, as applicable.

16. Issue of Gramin Rozgar Guarantee Card–

1. It shall be the duty of the Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a Gramin Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of such application, containing therein a unique Gramin Rozgar Guarantee Card number with details of the registered adult members of the household, their photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and the Aadhaar numbers, if any.

2. The Gramin Rozgar Guarantee Card issued, shall be valid for three years,

3. after which it may be renewed after due verification.

4. No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on any of the following grounds-

- (i) Where it is found to be a duplicate;
- (ii) Where the entire household has permanently migrated to a place outside the jurisdiction of the Gram Panchayat and no longer resides in the village;
- (iii) Where all adult members of the registered household are deceased.

5. The State Government shall make arrangements for updating the following details in the Gramin Rozgar Guarantee Card regularly while mentioning the key guarantees under the Scheme are clearly listed as follows: –

- (i) Number of days for which work was demanded;
- (ii) Number of days of work allocated;
- (iii) Description of the work allocated along with the muster roll number;
- (iv) Measurement details;
- (v) Unemployment allowance, if any, paid;
- (vi) Date-wise amount of wages paid;
- (vii) Delay compensation paid if any;
- (viii) Asset provided, if any.

6. Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

17. Issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in Case of Dislocation–

1. Notwithstanding anything contained in this Schedule, in the event of any national calamity such as flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting in mass dislocation of rural population, the adult members of rural households of areas so affected may–

- (i) seek for registration and get Gramin Rozgar Guarantee Card issued by the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;
- (ii) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation;
- (iii) apply for re-registration and re-issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in the event of any loss or destruction.

2. The details of such Gramin Rozgar Guarantee Cards shall be intimated to the District Programme Coordinator.

3. In the event of restoration of normalcy, the Gramin Rozgar Guarantee Card so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and clubbed with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

4. The number of days of employment provided shall be counted while computing 125 days of guaranteed employment per household.

CHAPTER- VII

DEMAND FOR WORK AND ALLOTMENT

18. Demand for Work–

1. Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

2. The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

3. Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

4. Applications for work may be filed individually or for a group together.

5. There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate guarantee of the household.

6. Normally, applications for work must be for at least six days of continuous work.

7. Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is, application which may be submitted earlier than the date from which employment is sought.

8. Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

19. Allocation of Work–

1. The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later.

2. Priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work. Efforts to increase participation of single women and the person with disabilities shall be made.

3. Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

4. A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

5. As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

6. A new work under the Scheme can be commenced if at least ten labourers become available for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation works.

7. In case the employment is provided outside the radius of five kilometers, the labourers shall be paid ten percent of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expenses for living.

8. A period of employment shall be for at least six days continuously, with not more than six days in a week.

CHAPTER VIII

MUSTER ROLLS, ATTENDANCE AND MEASUREMENT

20. Muster rolls—

The muster rolls for works undertaken under this Scheme shall be maintained through digital systems and shall comply with the following requirements -

(a) Each muster roll shall be in English and the local language and have a unique electronically generated identity number (e-muster) issued through the management information system.

(b) The muster roll shall include the names of all workers who have demanded or been allocated work and shall be authenticated by the authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

21. Attendance recording—

Attendance at the worksite shall be recorded daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis through the designated management information system.

22. Measurement of work—

1. Payment of wages shall only be made based on measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within three days of the closure of the muster roll, and recorded digitally through systems integrated with the designated management information system.

2. The State Government shall ensure the deployment of adequate technical personnel to enable timely measurement. Suitable persons may be trained and deployed, with delegated technical responsibilities, and shall be paid wages at skilled rates.

CHAPTER - IX

WAGE PAYMENT AND DELAY COMPENSATION

23. Wage payment—

1. Wage rate to be paid to the worker will be decided and notified by the Central Government.

2. The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

24. Mode of payment—

The payment of wages shall, unless so exempted by the Central Government, be made through the individual savings accounts of the workers in the relevant Banks or Post Offices

25. Delay compensation—

1. In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

2. Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages.

3. For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages such as,—

- (i) Measurement of work;
- (ii) Computerising the muster rolls;
- (iii) Computerising the measurements;
- (iv) Generation of wage lists; and

(v) Uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function.

4. The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

5. District Programme Coordinator and Programme Officer shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who are responsible for the delay in payment.

6. The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the Management Information System.

CHAPTER - X

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

26. Eligibility—

1. If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of this section.

2. No such rate shall be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.

27. Procedure—

The unemployment allowance payable to the household of an applicant jointly, shall be sanctioned and disbursed by the Programme Officer or such local authority (including the Panchayat at the District, intermediate or village level).

Every payment of unemployment allowance shall be made or offered not later than fifteen days from the date on which it became due for payment.

CHAPTER - XI

CATEGORIES OF WORKS & ELIGIBILITY CRITERIA FOR INDIVIDUAL BENEFICIARY WORK

28. Works & Categories under the Scheme—

1. Focus of the Scheme—Classification of Works: The Scheme shall focus on the following categories of works, as identified in the Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

2. The works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following Categories, together with their thematic focus and intended outcomes, namely:—

A. Category I-Water-Related Works (for Water Security) –

(a) The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge, source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development and afforestation and the Illustrative works include—

(i) Construction of canals, flood or diversion channels, check dams, gully plugs and underground dykes;

(ii) Construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks, recharge pits, recharge shafts, injection wells and associated water harvesting structures;

(iii) Irrigation open wells, micro-irrigation channels and field water distribution systems;

(iv) Reclamation of community waterlogged land;

(v) Afforestation and plantation works linked with soil and moisture conservation;

(vi) Rooftop rainwater harvesting and other decentralised; and

(vii) Recharge systems.

(b) Intended Outcomes—Strengthening of water security through integrated water resource management, recharge and conservation for long-term climate resilience.

B. Category II-Core Rural Infrastructure–

(a) Thematic focus shall include core civic, social, governance and service-delivery infrastructure relating to education, health, drinking water, sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the Illustrative works include–

- (i) Construction or upgradation of rural roads, culverts, cross- drainage structures and village connectivity facilities;
- (ii) Construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, rural libraries and other public buildings;
- (iii) Construction of school infrastructure, including kitchen sheds, additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds;
- (iv) Crematoria and community infrastructure;
- (v) Solid and liquid waste management assets, including stabilising ponds, community sanitary complexes, and waste segregation and collection centres;
- (vi) Installation of solar lighting systems and other renewable rural energy infrastructure;
- (vii) Village parking areas, transport sheds and other common rural amenities;
- (viii) Rural housing works permissible under the schemes of the Central Government, including those permitted under the Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin;
- (ix) Repair and maintenance of works created under the Jal Jeevan Mission for ensuring water supply.

(b) Intended Outcome-Creation of foundational civic and social infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced quality of life in rural areas.

C. Category III-Livelihood-related Infrastructure–

(a) Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition, skilling and enterprise development and the Illustrative works include–

- (i) Construction of training-cum-skill development centres and work sheds for livelihood activities;
- (ii) Rural haats or weekly markets and other market infrastructure;
- (iii) Food grain storage buildings, agricultural produce storage structures, cold storage units and other agri-value chain infrastructure;
- (iv) Buildings for Self Help Groups and federation-level institutions;
- (v) Compost structures, including vermicompost and NADEP units;
- (vi) Development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;
- (vii) Fisheries-related infrastructure, including fish drying yards;
- (viii) Raising of nurseries and production of building material; and
- (ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as may be approved by the Central Government.

(b) Intended Outcome-Strengthening of sustainable livelihoods, value addition, enterprise development and self-reliant rural economies.

D. Category IV-Special works to mitigate Extreme Weather Events and Disaster Preparedness–

(a) Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation, and protection of rural communities and assets from floods, cyclones, storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events and the Illustrative works include–

- (i) Construction of cyclone shelters, flood shelters and multipurpose disaster resilient structures;
- (ii) Construction of diversion channels, embankments and other disaster- mitigation works;
- (iii) Stabilising ponds and water structures for flood management;

(iv) Post-disaster rehabilitation, restoration and repair of rural roads and community assets;

(v) Windbreak and shelterbelt plantations; and

(vi) Forest fire management works, including fire

(vii) Breaks, fuel buffer zones and allied measures.

(b) Intended Outcome Creation of climate-resilient villages capable of withstanding extreme weather conditions.

3. Any other public work which may be notified by the Central Government.

4. Maintenance of rural public assets created under the Act.

5. Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing- related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin, sanitation-related works, and other beneficiary-oriented developmental works undertaken under various schemes of the Central Government from time to time and expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government, aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards and guidelines issued by the Central Government.

29. Eligibility Criteria of the Beneficiary for Individual Beneficiary Work–

Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to–

(i) The Scheduled Castes;

(ii) The Scheduled Tribes;

(iii) Nomadic tribes;

(iv) Denotified tribes;

(v) Economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government;

(vi) Women-headed households;

(vii) Households headed by persons with disabilities;

(viii) Beneficiaries of land reforms;

(ix) Beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin (PMAY-G); and

(x) Beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and

After exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

CHAPTER - XII

WORKSITE MANAGEMENT AND SAFETY

30. Facilities at worksites–

1. For the purpose of transparency at the worksite, the following shall be ensured–

(i) There shall be a project initiation meeting in which various provisions of the work shall be explained to the workers;

(ii) A copy of the sanction work order shall be available for public inspection at the worksite;

(iii) Measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection;

(iv) A Citizens' Information Board shall be put up at every worksite and

(v) Updated regularly in the manner specified by the Central Government;

(vi) The vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the Central Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the Central Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

2. The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the worksite.

3. In case the number of children below the age of five years accompanying the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate.

31. Safety and accidents—

1. If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required, free of cost.

2. Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half of the wage rate.

3. If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an ex gratia as per entitlement under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana or as may be notified by the Central Government.

4. If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

CHAPTER - XIII

RESTRICTION ON UNDERTAKING WORKS DURING PEAK AGRICULTURAL SEASONS

32. Notification of Peak Agricultural Seasons—

The State Government shall, in advance of each financial year, notify a period or periods aggregating to sixty days in a financial year, covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting, during which no works under the Scheme shall be undertaken.

33. Area-Specific Notifications—

1. The State Government may issue distinct notifications for different areas of the State, including districts, blocks or Gram Panchayats, having regard to—

- (i) Agro-climatic zones;
- (ii) Local patterns of agricultural activities; and
- (iii) Such other relevant factors as may be considered necessary.

2. Every notification issued under this provision shall have binding effect for the purposes of the Act and the Scheme.

34. Prohibition on Works during Notified Periods—

All authorities responsible for planning, sanctioning or executing works under the Scheme shall ensure that no work is undertaken during the periods notified as peak agricultural seasons.

35. Scheduling of Works—

The Programme Officer and other implementing authorities shall, while approving the aggregated Viksit Gram Panchayat Plans and scheduling works, ensure that all works are taken up only outside the notified peak agricultural seasons.

CHAPTER - XIV

ESTIMATE, SANCTIONING AND WORK EXECUTION**36. ESTIMATES-**

1. Technical Estimates and Standards for Works-Every work under this Scheme shall have a technical estimate and design sanctioned by an authority authorised by the State Government, based on the framework aligned with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

2. For works involving construction, appropriate labour-intensive technologies, depending upon the availability of labour and the use of local materials, shall be employed to the extent feasible.

3. Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology to ensure transparency for all stakeholders.

4. Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note indicating the expected outputs and outcomes.

5. All technical estimates, designs and outcome notes shall be generated or uploaded through digital systems integrated with the designated management information system.

37. Administrative and Financial Sanctions -

1. Works finalised at the Gram Panchayat level through the approved Viksit Gram Panchayat Plan and aggregated at the Block and District levels shall be accorded administrative or financial sanction by the competent authority as per the requirements and within thirty days.

2. The sanctioning authorities shall ensure that-

(i) The proposed works are drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan;

(ii) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

(iii) The works are consistent with thematic domains, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack;

(iv) All sanctioned works are taken up through the designated digital portal under the Act.

38. Wage Linkage to Output and Schedule of Rates-

The State Government shall ensure that wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed, in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of time-and-motion studies for different types of work and different seasons, and revised periodically.

39. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups -

A separate Schedule of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities and persons with debilitating ailments to facilitate their productive participation in suitable categories of work.

40. Working Hours and Earning Norms-

1. The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

2. Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

41. Inspection and Quality Control -

The State Government shall ensure regular inspection and supervision of works by designated quality-control teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements and conformity of wage payments to the actual quantum of work executed. Inspection reports shall be uploaded to the management information system.

42. Completion of Ongoing Works -

At the time of opening new works, it shall be ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion, subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

43. Wage-Material Ratio-

For all works taken up under the scheme, by the Gram Panchayats and other implementing agencies, the cost of material component shall not exceed forty percent at the district level.

44. Execution Without Contractors-

1. No contractor shall be engaged for the execution of any work or component financed through expenditure under this Act. All such works shall be executed directly by the implementing agencies in accordance with the processes laid down under the Scheme, including mandatory proactive disclosures and the social audit process.

2. In cases of convergence where components of a work are financed under other schemes, the execution of those components may follow the norms of the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

3. As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

45. Transparent Procurement of Materials -

All materials required for the execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency through transparent procurement systems, including e-tendering processes, as specified by the State Government.

CHAPTER - XV**FUNDING PATTERN AND FINANCIAL ARRANGEMENTS****46. Funding Pattern-**

1. Centrally Sponsored Scheme: The Scheme shall be implemented as a Centrally Sponsored Scheme.

2. Cost Sharing between the Central Government and the State Government

a. The funding pattern under the Scheme shall be as under:

(i) 90:10 between the Central Government and the State Government in respect of North Eastern States, Himalayan States and the Union Territories of Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh; and

(ii) 60:40 between the Central Government and the State Government in respect of all other States and Union territories with legislature.

b. In respect of Union territories without legislature, the Central Government shall bear the entire expenditure on the Scheme.

47. Financial Arrangements-

1. State-wise Normative Allocation: The Central Government shall determine, for every financial year, a State-wise normative allocation for implementation of the Scheme, based on such objective parameters as may be communicated from time to time.

2. Expenditure Beyond Normative Allocation: Any expenditure incurred by the State Government over and above the State-wise normative allocation shall be borne by the State Government.

3. Central Share: The share of the Central Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards-

(a) Payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

(b) The material component of works, subject to the provisions contained in Schedule-I; and

(c) Such administrative expenses as may be specified by the Central Government, including-

(i) Salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,

(ii) Administrative expenses of the Central Council,

(iii) Facilities required under Schedule-II, and

(iv) such other items.

4. State Share: The share of the State Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards-

(a) Payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

(b) The material component of works, subject to Schedule-I; and

(c) Such administrative expenses as may be specified, including-

- (i) Salary and allowances of Programme Officers and supporting staff,
- (ii) Administrative expenses of the State Council,
- (iii) Facilities required under Schedule-II, and
- (iv) Such other items.

5. Unemployment Allowance and Delay Compensation: The State Government shall bear the expenditure towards unemployment allowance and delay compensation payable under the Scheme, as per the provisions notified/issued by the State Government.

6. Intra-State distribution of normative Allocation - The State Government shall, upon receipt of the approved normative allocation from the Central Government, ensure equitable, need-based and transparent intra-State distribution of the allocation across districts and Gram Panchayats, taking into consideration the categorisation of Gram Panchayats and the assessed local needs for determining Gram Panchayat-wise allocations and corresponding district allocations; and the detailed methodology, parameters and procedural requirements for such distribution shall be notified by the Central Government.

7. Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Gram Rozgar Sahayak, other technical personnel as per the work done and for other administrative expenses.

CHAPTER - XVI

TRANSPARENCY AND PUBLIC DISCLOSURE

48. Proactive disclosure-

1. Mandatory Public disclosure shall be undertaken through digital systems integrated with the designated management information system and displayed at the village level for public scrutiny.

2. Display at every worksite a "Janata Board" indicating details of the work, estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise costs.

3. Digital and physical display of number of days of employment provided, wage payments, material payments, guarantees under the Act, works approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year-wise works taken up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

4. Public disclosure of all information relating to works, labour demand, employment provided, payments, material utilisation and physical progress under this Scheme shall be carried out through digital systems integrated with the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and displayed in a publicly accessible physical and digital formats.

In addition, the Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram Panchayat Bhawan to present the status of works, payments, grievances and other relevant information before the community.

5. District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure that their official websites are regularly updated in compliance with Clause (b) of sub-section (1) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), with all information on the Act available in free, downloadable electronic form.

6. All accounts and records including muster rolls relating to the scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt of application.

CHAPTER - XVII

SOCIAL AUDIT

49. Conduct of Social Audit-

1. All works, expenditures and guarantees under this Scheme shall be subject to social audit at least once every six months.

2. The procedure, standards and modalities for conducting social audits shall be as per the rules notified by the Central Government.

3. Until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall, mutatis mutandis, apply to the conduct of social audits under this Act.

50. Compliance with findings-

1. Findings of the social audit shall be placed in the Gram Sabha.
2. Corrective and recovery actions shall be initiated without delay.
3. Action-taken reports shall be recorded in the MIS.
4. Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.
5. The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

51. Annual Reporting-

The District Programme Coordinator, the Programme Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts, figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

CHAPTER - XVIII

GRIEVANCE REDRESSAL AND OMBUDSPERSON

52. Grievance Redressal Mechanism:-

An effective grievance redressal mechanism shall be established under the Scheme, comprising the following components, namely:

1. Institutional mechanisms for receiving grievances at the Ward, Gram Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day each week when officials shall be mandatorily available to receive grievances;
2. Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.
3. Issuance of a dated acknowledgement for all grievances submitted in writing, telephonically, online, or orally to any authorised functionary;
4. Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be completed within seven working days of receipt of the grievance;
5. Upon completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate immediate corrective action, and the grievance shall be resolved within fifteen days;
6. Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level determined, shall be treated as a contravention of the provisions of this Act;
7. Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;
8. The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;
9. Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;
10. Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall lie before the District Programme Coordinator;
- appeals against the orders of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance Redressal Authority or any officer designated by the State Government;
11. All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order;
12. All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt;

13. Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next higher level through digital systems integrated with the designated management information system, and such escalations shall be continuously monitored electronically.

53. Record maintenance and grievance redressal system -

The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat.

54. Ombudsperson-

The State Government shall appoint an Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries and issue awards in accordance with the guidelines notified by the Central and the State Governments. The Ombudsperson shall operate through digital platforms integrated with the designated digital portal under this Act.

CHAPTER - XIX

MONITORING, INSPECTION AND EVALUATION

55. Monitoring-

1. The State Government shall monitor implementation at State, District and Block levels.
2. Dashboards and analytical reports shall be maintained in the MIS.

56. Inspections-

A minimum prescribed percentage of works at each level shall be inspected every year.

- (i) At Gram Panchayat Level- 100% of works executed during the year shall be inspected.
- (ii) At Block Level- At least 60% of works executed in different Gram Panchayats of the respective Block shall be inspected.
- (iii) At District Level- At least 10% of works executed in different Gram Panchayats of the respective District shall be inspected.
- (iv) At State Level- At least 2% of works executed in different Gram Panchayats across the State shall be inspected.

57. Evaluation-

1. Independent evaluations shall be undertaken periodically to assess outcomes and impact.
2. For ensuring measurable outcomes and real-time accountability, technology-enabled monitoring shall be mandated for tracking work execution and post-completion asset outcomes, supported by verified data systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be reinforced through a comprehensive transparency framework. A Concurrent Evaluation Mechanism as specified by the Central Government, shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

58. Penalties for contravention and recovery of misappropriated amounts-

1. Whoever contravenes any provision of the Act, shall be liable to pay the penalty which may extend to ten thousand rupees.
2. Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant laws for recovery prevailing in the state.
3. The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

CHAPTER - XX

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

59. Training and Capacity Building-

1. The State Government shall prepare and implement a dedicated plan for capacity building and strengthening of Panchayati Raj Institutions for effective planning, execution, supervision and monitoring of the Scheme.

2. The capacity-building plan shall, inter alia, include activities relating to:
 - (i) Training of elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions on roles and responsibilities under the Scheme;
 - (ii) Information, Education and Communication (IEC) initiatives to enhance awareness regarding the provisions of the Scheme, transparency mechanisms and community participation;
 - (iii) Digital literacy and orientation on the use of Management Information Systems, geo-tagging tools and other digital platforms;
 - (iv) Strengthening institutional systems in Panchayati Raj Institutions for record keeping, financial management, grievance redressal, social audit and asset maintenance.
3. The plan shall be prepared annually, based on field requirements, and shall be integrated with the State Training and Capacity Building framework under the Scheme.
4. Panchayati Raj Institutions shall extend full cooperation in organising such capacity- building initiatives and shall ensure participation of elected representatives and functionaries.
5. Expenditure on activities undertaken under this provision shall be met from permissible administrative and capacity-building heads, as may be specified by the Central Government and the State Government.

CHAPTER - XXI

CLOSING FORMULA

This Scheme shall be read harmoniously with the provisions of the Act. In the event of any inconsistency, the provisions of the Act shall prevail.

By order,
SORABH BABU,
Pramukh Sachiv.

SCHEDULE-I

[See section 8(3)]

Minimum features of Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission
(Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Scheme

1. The Scheme notified under section 8 of the Act by all States shall be called the “Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin):

VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Scheme” and all documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.

2. All Scheme documents pertaining to the said Scheme shall have a mention of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025.

3. The core objectives of the Scheme shall be as follows:—(a) The primary objective of this Act is to align the rural development framework with the national vision of Viksit Bharat @2047 by providing an enhanced statutory wageemployment guarantee of one hundred and twenty-five days in each financial year to such rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to participate more effectively in the expanded livelihood security framework.

(b) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through public works aggregating into forming Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security through water-related works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and special works to mitigate extreme weather events.

(c) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons, and, in view of the wage-employment guarantee for the rural workforce.

(d) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole of government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with the PM Gati Shakti to address the varying needs of Gram Panchayats, powered by geospatial systems, digital public infrastructure, district and State planning mechanisms, with such plans aggregated at the Block, District, State and National levels.

(e) To modernise governance, accountability and citizen engagement through a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication at various levels, global positioning system or mobile based worksite monitoring, real time management information system dashboards, proactive public disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud risk mitigation.

4. Works under the Scheme—(1) Focus of the Scheme—Classification of Works: The Scheme shall focus on the following categories of works, as identified in the Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) For the purposes of section 4 of the Act, the works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following Categories, together with their thematic focus and intended outcomes, namely:—

(a) Category I—Water-Related Works (for Water Security)—

(A) The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge, source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development and afforestation and the Illustrative works include—

(i) construction of canals, flood or diversion channels, check dams, gully plugs and underground dykes;

(ii) construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks, recharge pits, recharge shafts, injection wells and associated water harvesting structures;

(iii) irrigation open wells, micro-irrigation channels and field water distribution systems;

(iv) reclamation of community waterlogged land;

(v) afforestation and plantation works linked with soil and moisture conservation; and

(vi) rooftop rainwater harvesting and other decentralised recharge systems.

(B) Intended Outcomes—Strengthening of water security through integrated water resource management, recharge and conservation for long-term climate resilience.

(b) Category II—Core Rural Infrastructure—

(A) Thematic focus shall include core civic, social, governance and service-delivery infrastructure relating to education, health, drinking water, sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the Illustrative works include—

(i) construction or upgradation of rural roads, culverts, crossdrainage structures and village connectivity facilities;

(ii) construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, rural libraries and other public buildings;

(iii) construction of school infrastructure, including kitchen sheds, additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds;

(iv) crematoria and community infrastructure;

(v) solid and liquid waste management assets, including stabilising ponds, community sanitary complexes, and waste segregation and collection centres;

(vi) installation of solar lighting systems and other renewable rural energy infrastructure;

(vii) village parking areas, transport sheds and other common rural amenities;

(viii) rural housing works permissible under the schemes of the Central Government, including those permitted under the Pradhan Mantri Awas Yojana—Gramin; and

(ix) repair and maintenance of works created under the Jal Jeevan Mission for ensuring water supply.

(B) Intended Outcome—Creation of foundational civic and social infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced quality of life in rural areas.

(c) Category III—Livelihood-related Infrastructure—

(A) Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition, skilling and enterprise development and the Illustrative works include—

- (i) construction of training-cum-skill development centres and work sheds for livelihood activities;
- (ii) rural haats or weekly markets and other market infrastructure;
- (iii) food grain storage buildings, agricultural produce storage structures, cold storage units and other agri-value chain infrastructure;
- (iv) buildings for Self Help Groups and federation-level institutions;
- (v) compost structures, including vermicompost and NADEP units;
- (vi) development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;
- (vii) fisheries-related infrastructure, including fish drying yards;
- (viii) raising of nurseries and production of building material; and
- (ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as may be approved by the Central Government.

(B) Intended Outcome—Strengthening of sustainable livelihoods, value addition, enterprise development and self-reliant rural economies.

(d) Category IV—Special works to mitigate Extreme Weather Events and Disaster Preparedness—

(A) Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation, and protection of rural communities and assets from floods, cyclones, storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events and the Illustrative works include—

- (i) construction of cyclone shelters, flood shelters and multipurpose disaster resilient structures;
- (ii) construction of diversion channels, embankments and other disaster-mitigation works;
- (iii) stabilising ponds and water structures for flood management;
- (iv) post-disaster rehabilitation, restoration and repair of rural roads and community assets;
- (v) windbreak and shelterbelt plantations; and
- (vi) forest fire management works, including fire breaks, fuel buffer zones and allied measures.

(B) Intended Outcome—Creation of climate-resilient villages capable of withstanding extreme weather conditions.

(3) Any other public work which may be notified by the Central Government.

(4) Maintenance of rural public assets created under the Act.

(5) Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing-related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin, sanitation-related works, and other beneficiary-oriented developmental works undertaken under various schemes of the Central Government from time to time and expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government, aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards and guidelines issued by the Central Government.

(6) Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to—

- (a) the Scheduled Castes;
- (b) the Scheduled Tribes;
- (c) nomadic tribes;
- (d) denotified tribes;
- (e) economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government;
- (f) women-headed households;
- (g) households headed by persons with disabilities;
- (h) beneficiaries of land reforms;
- (i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-G); and
- (j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and

after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

5. Participatory Planning under the Scheme:—(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central Government for the purpose of convergence and saturation-based planning, shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(2) There shall be a systematic and participatory planning exercise undertaken at each tier of the Panchayati Raj system in accordance with the specified methodology. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by the Gram Panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval. Works proposed to be undertaken by the Intermediate Panchayat, District Panchayat or other implementing agencies shall likewise be placed before the respective Panchayats along with the expected outputs and outcomes. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural development strategies, and saturation-based planning for comprehensive coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats. All works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack.

(3) Viksit Gram Panchayat Plan—Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its classification into Category A, B, C, *etc.*, determined based on development parameters, including proximity to urban areas, to address the varying needs of the Panchayats. All such works shall be drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan, prepared using PM Gati Shakti, GIS-based tools and other digital public infrastructure.

(4) The works identified in the Viksit Gram Panchayat Plans shall be executed through various Central, State and local schemes in convergence. The schemes to be taken up for such convergence shall be notified by the Central Government.

6. Framework for Convergence and Integrated Planning—A Unified Convergence Framework shall be established for coherent planning, execution and monitoring of all works undertaken in rural areas, and for this purpose—

(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central Government for the purpose of convergence and saturation-based planning, shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(2) All existing assets and proposed works, whether funded under this Act or through any other Central, State or local scheme, shall be mandatorily registered and tracked through the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack using the designated digital portal, which shall maintain a comprehensive register of rural public works, prevent duplication, integrate departmental investments, and align all works with saturation outcomes.

(3) The Ministry of Rural Development shall prepare and periodically update the management information system, a nationally harmonised, single digital backbone for rural public works covering water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events; and all planning shall follow a strict bottom-up process beginning with the preparation of the Viksit Gram Panchayat Plan, which shall be successively aggregated at the Block, District and State levels, and the aggregated State Plan shall be placed before the State Level Steering Committee for approval.

(4) Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States, Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments contribute measurably to saturation outcomes at the Gram Panchayat, Block and District levels.

(5) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding approach, promote convergence across departments and schemes, and align all rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision of creating productive, resilient and transformative rural assets.

7. Intra-State distribution of normative Allocation—The State Government shall, upon receipt of the approved normative allocation from the Central Government, ensure equitable, need-based and transparent intra-State distribution of the allocation across districts and Gram Panchayats, taking into consideration the categorisation of Gram Panchayats and the assessed local needs for determining Gram Panchayat-wise allocations and corresponding district allocations; and the detailed methodology, parameters and procedural requirements for such distribution shall be notified by the Central Government.

8. Completion of Ongoing Works—At the time of opening new works, it shall be ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion, subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

9. Technical Estimates and Standards for Works—Every work under this Act shall have a technical estimate and design sanctioned by an authority authorised by the State Government, based on the framework aligned with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

10. For works involving construction, appropriate labour-intensive technologies, depending upon the availability of labour and the use of local materials, shall be employed to the extent feasible.

11. Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology to ensure transparency for all stakeholders.

12. Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note indicating the expected outputs and outcomes.

13. All technical estimates, designs and outcome notes shall be generated or uploaded through digital systems integrated with the designated management information system.

14. Administrative and Financial Sanctions—(1) Works finalised at the Gram Panchayat level through the approved Viksit Gram Panchayat Plan and aggregated at the Block and District levels shall be accorded administrative or financial sanction by the competent authority as per the requirements and within thirty days.

(2) The sanctioning authorities shall ensure that—

(a) the proposed works are drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan;

(b) the works are consistent with thematic domains, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack;

(c) all sanctioned works are taken up through the designated digital portal under the Act.

15. Muster Rolls and Attendance Systems—The muster rolls for works undertaken under this Act shall be maintained through digital systems and shall comply with the following requirements—

(a) Each muster roll shall be in English and the local language and have a unique electronically generated identity number (e-muster) issued through the management information system. The muster roll shall include the names of all workers who have demanded or been allocated work and shall be authenticated by the authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

(b) Attendance at the worksite shall be recorded daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis through the designated management information system.

(c) e-Muster rolls shall be processed by officials in the manner stipulated under the relevant guidelines.

16. Measurement and Basis for Payment—(1) Payment of wages shall only be made based on measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within three days of the closure of the muster roll, and recorded digitally through systems integrated with the designated management information system.

(2) The State Government shall ensure the deployment of adequate technical personnel to enable timely measurement. Suitable persons may be trained and deployed, with delegated technical responsibilities, and shall be paid wages at skilled rates.

17. Wage Linkage to Output and Schedule of Rates—The State Government shall ensure that wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed, in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of time-and-motion studies for different types of work and different seasons, and revised periodically.

18. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups—A separate Schedule of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities and persons with debilitating ailments to facilitate their productive participation in suitable categories of work.

19. Working Hours and Earning Norms—(a) The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

(b) Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

20. Material Component—For all works undertaken under this Act, the cost of the material component shall not exceed forty per cent. at the District level.

21. Execution Without Contractors—(1) No contractor shall be engaged for the execution of any work or component financed through expenditure under this Act. All such works shall be executed directly by the implementing agencies in accordance with the processes laid down under the Act, including mandatory proactive disclosures and the social audit process.

(2) In cases of convergence where components of a work are financed under other schemes, the execution of those components may follow the norms of the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

22. As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

23. Transparent Procurement of Materials—All materials required for the execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency through transparent procurement systems, including e-tendering processes, as specified by the State Government.

24. Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Gram Rozgar Sahayak, other technical personnel as per the work done and for other administrative expenses.

25. Transparency and Accountability—(1) Every Scheme prepared under this Act shall contain comprehensive provisions to ensure transparency and accountability at all levels of implementation, including Mandatory Public Disclosure and social audit.

(2) Mandatory Public Disclosure—(a) Mandatory Public disclosure shall be undertaken through digital systems integrated with the designated management information system and displayed at the village level for public scrutiny.

(b) Display at every worksite a “Janata Board” indicating details of the work, estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise costs.

(c) Digital and physical display of number of days of employment provided, wage payments, material payments, guarantees under the Act, works approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year-wise works taken up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

(d) Public disclosure of all information relating to works, labour demand, employment provided, payments, material utilisation and physical progress under this Act shall be carried out through digital systems integrated with the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and displayed in a publicly accessible physical and digital formats. In addition, the Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram Panchayat Bhawan to present the status of works, payments, grievances and other relevant information before the community.

(e) The Ministry of Rural Development and the State Departments shall ensure that their official websites are regularly updated in compliance with Clause (b) of sub-section (1) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), with all information on the Act available in free, downloadable electronic form.

(3) Social audit—(a) all works, expenditures and guarantees under this Act shall be subject to social audit at least once every six months in the manner as may be prescribed by the Central Government;

(b) the procedure, standards and modalities for conducting social audits shall be as prescribed in the rules made under this Act;

(c) until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall, *mutatis mutandis*, apply to the conduct of social audits under this Act.

(4) Concurrent evaluation mechanism—For ensuring measurable outcomes and real-time accountability, technology-enabled monitoring shall be mandated for tracking work execution and post-completion asset outcomes, supported by verified data systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be reinforced through a comprehensive transparency framework. A Concurrent Evaluation Mechanism, as may be specified by the Central Government through guidelines, shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

26. Recovery of misappropriated amounts—(1) Any misappropriation of amounts spent under the Act shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(2) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

27. Inspection and Quality Control—The State Government shall ensure regular inspection and supervision of works by designated quality-control teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements and conformity of wage payments to the actual quantum of work executed. Inspection reports shall be uploaded to the management information system.

28. Grievance Redressal Mechanism—An effective grievance redressal mechanism shall be established under the Act, comprising the following components, namely:—

(a) Institutional mechanisms for receiving grievances at the Ward, Gram Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day each week when officials shall be mandatorily available to receive grievances;

(b) Issuance of a dated acknowledgement for all grievances submitted in writing, telephonically, online, or orally to any authorised functionary;

(c) Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be completed within seven working days of receipt of the grievance;

(d) Upon completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate immediate corrective action, and the grievance shall be resolved within fifteen days;

(e) Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level determined, shall be treated as a contravention of the provisions of this Act and shall attract action in accordance with Section 27 or any corresponding provision of this Act;

(f) Where *prima facie* evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;

(g) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;

(h) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;

(i) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall lie before the District Programme Coordinator; appeals against the orders of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance Redressal Authority or any officer designated by the State Government;

(j) All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order;

(k) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt;

(l) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next higher level through digital systems integrated with the designated management information system, and such escalations shall be continuously monitored electronically.

29. Ombudsperson—The State Government shall appoint an Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries and issue awards in accordance with the guidelines notified by the Central and the State Governments. The Ombudsperson shall operate through digital platforms integrated with the designated digital portal under this Act.

30. Action for Contravention—Wherever contravention of any provision of this Act is established after due enquiry by the State Government, the District Programme Coordinator, the Programme Officer, the Ombudsperson or any other authority authorised by the State Government, action shall be taken in accordance with Section 27 of this Act or any corresponding provision.

31. Annual Reporting—The District Programme Coordinator, the Programme Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts, figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

32. All accounts and records including muster rolls relating to the scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt of application.

33. Capacity Building and Strengthening Panchayats—There shall be a dedicated plan for training, Information Education Communication, digital literacy and strengthening Panchayati Raj Institutions.

SCHEDULE-II

[See section 9(2)]

1. Gramin Rozgar Guarantee Card—(1) Household Registration—The adult member of every household residing in any rural area and willing to undertake unskilled manual work, may submit the names, ages and address of the household to the Gram Panchayat within whose jurisdiction they reside, for the purpose of registration of the household and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card.

(2) Special Gramin Rozgar Guarantee Card, where the job seeker is—

- (a) a single woman; or
- (b) a person with disability; or
- (c) persons above sixty years of age; or
- (d) a released bonded labourer; or
- (e) a person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group; or
- (f) a transgender person.

(3) The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour, shall ensure special protection in the providing work, work evaluation, and worksite facilities, as applicable.

(4) It shall be the duty of the Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a Gramin Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of such application, containing therein a unique Gramin Rozgar Guarantee Card number with details of the registered adult members of the household, their photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and the Aadhaar numbers, if any.

(5) The Gramin Rozgar Guarantee Card issued, shall be valid for three years, after which it may be renewed after due verification.

(6) No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on any of the following grounds:—

- (a) where it is found to be a duplicate;
- (b) where the entire household has permanently migrated to a place outside the jurisdiction of the Gram Panchayat and no longer resides in the village; or
- (c) where all adult members of the registered household are deceased.

(7) The State Government shall make arrangements for updating the following details in the Gramin Rozgar Guarantee Card regularly while mentioning the key guarantees under the Act are clearly listed as follows:—

- (a) number of days for which work was demanded;
- (b) number of days of work allocated;
- (c) description of the work allocated along with the muster roll number;
- (d) measurement details;
- (e) unemployment allowance, if any, paid;
- (f) date-wise amount of wages paid;
- (g) delay compensation paid if any;
- (h) asset provided, if any.

2. Demand for work—(1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

(5) There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate guarantee of the household.

(6) Normally, applications for work must be for at least six days of continuous work.

(7) Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is, application which may be submitted earlier than the date from which employment is sought.

(8) Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

3. Allocation of work—(1) The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later.

(2) Priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work. Efforts to increase participation of single women and the person with disabilities shall be made.

(3) Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

(4) A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

(5) As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

(6) A new work under the Scheme can be commenced if at least ten labourers become available for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation works.

(7) In case the employment is provided outside the radius specified in sub-paragraph (5) of paragraph 3, it shall be provided within the Block, and the labourers shall be paid ten percent. of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expenses for living.

(8) A period of employment shall be for at least six days continuously, with not more than six days in a week.

4. Worksite management—(1) For the purpose of transparency at the worksite, the following shall be ensured—

(a) there shall be a project initiation meeting in which various provisions of the work shall be explained to the workers;

(b) a copy of the sanction work order shall be available for public inspection at the worksite;

(c) measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection;

(d) a Citizens' Information Board shall be put up at every worksite and updated regularly in the manner specified by the Central Government;

(e) the vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the Central Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the Central Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

(2) The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the worksite.

(3) In case the number of children below the age of five years accompanying the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate.

5. Welfare—(1) If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required, free of cost.

(2) Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalisation including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half of the wage rate.

(3) If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an *ex gratia* as per entitlement under the *Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana* or as may be notified by the Central Government.

(4) If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, *ex gratia* shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

6. Wage payment—(1) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

(2) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages.

(3) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages such as,—

(a) measurement of work;

(b) computerising the muster rolls;

(c) computerising the measurements;

(d) generation of wage lists; and

(e) uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function.

(4) The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

(5) The State Government shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who are responsible for the delay in payment.

(6) It shall be the duty of the District Programme Coordinator or Programme Officer to ensure that the system is operationalise.

(7) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the Management Information System.

(8) Effective implementation of sub-paragraph (1) shall be considered necessary for the purposes of Section 29 of the Act.

7. The payment of wages shall, unless so exempted by the Central Government, be made through the individual savings accounts of the workers in the relevant Banks or Post Offices.

8. In case of employment provided under the Scheme, there shall be no discrimination solely on the ground of gender and the provisions of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), shall be complied with.

9. Record maintenance and grievance redressal system—The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat.

10. (1) Notwithstanding anything contained in this Schedule, in the event of any national calamity such as flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting in mass dislocation of rural population, the adult members of rural households of areas so affected may—

(a) seek for registration and get Gramin Rozgar Guarantee Card issued by the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;

(b) submit written or oral applications for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and

(c) apply for re-registration and re-issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in the event of any loss or destruction.

(2) The details of such Gramin Rozgar Guarantee Cards shall be intimated to the District Programme Coordinator.

(3) In the event of restoration of normalcy, the Gramin Rozgar Guarantee Card so issued shall be re-endorsed at original place of habitation and clubbed with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

(4) The number of days of employment provided shall be counted while computing 125 days of guaranteed employment per household.

11. Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

DR. RAJIV MANI,
Secretary to the Govt. of India.